वर्ष 13 • अंक 16 • 14 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

गुरुवार 5 मार्च 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

धातु व कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

टी कृष्णकुमार ▸▸ पृष्ठ 2

समृद्ध ग्राहकों के लिए नए उत्पाद लाएगी कोका-कोला

डॉलर रु. 73.20 ▼ 10 पैसे | यूरो रु. 81.60 ▲ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 43130 ▲ 854 रुपये | सेंसेक्स 38409.50 ▼ 214.20 | निफ्टी 11251.00 ▼ 52.30 | निफ्टी फ्यूचर्स 11247.10 ▼ 03.90 | ब्रेंट क्रूड 52.80 डॉलर ▲ 01.10 डॉलर

एक नज़र

सेवा क्षेत्र में सात साल की सबसे तेज वृद्धि

भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में लगातार पांचवें महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई। बुधवार को जारी मासिक सर्वेक्षण के अनुसार ऑर्डर में तेजी, निर्यात मांग बढ़ने और कारोबारी विश्वास मजबूत होने से यह वृद्धि दर्ज की गई। आईएचएस मार्किट इंडिया का सेवा कारोबार गतिविधि सूचकांक जनवरी के 55.5 से बढ़कर फरवरी में 57.5 हो गया। यह जनवरी 2013 से सेवा क्षेत्र में सबसे तेज बढ़ोतरी है। पृष्ठ 4

'विवाद से विश्वास' विधेयक को लोकसभा की मंजूरी

लोकसभा ने बुधवार को कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी। विपक्षी सदस्य दिल्ली हिंसा पर तत्काल चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। सदन में इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। पृष्ठ 4

एसबीआई कार्ड आईपीओ को 15 गुना बोलियां

शेयर बाजारों में उथलपुथल के बावजूद एसबीआई कार्ड्स ऐंड पेमेंट सर्विसेज के आईपीओ को संस्थागत निवेशकों ने हाथोहाथ लिया है। पात्र संस्थागत खरीदार श्रेणी में इसे 57 गुना बोलियां मिलीं और बोली की कुल राशि 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई। आईपीओ को कुल 15.2 गुना बोलियां मिली हैं। पृष्ठ 3

3,500 करोड़ रुपये टीडीएस डिफॉल्ट का मामला

आयकर विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रमुख तेल कंपनियों और दूरसंचार ऑपरेटर की जांच में 3,500 करोड़ रुपये स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के मामले में चूक का पता लगाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसकी जानकारी दी। सीबीडीटी ने कहा कि तेल कंपनी के मामले में 3,200 करोड़ रुपये के टीडीएस भुगतान में चूक का पता चला है।

दूरसंचार कंपनियां बिना देरी करें बकाया भुगतान

दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के मद में बकाया रकम का भुगतान बिना किसी देरी के करने का निर्देश दिया है। इन कंपनियों ने सरकार को अब तक एजीआर की रकम के तौर पर मात्र 15,896.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इस बीच, सरकार ने गेल, ओआईएल और सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को एजीआर आदेश से अलग कर दिया है।

कोरोनावायरस के खिलाफ कंपनी जगत ने कसी कमर

बीएस संवाददाता
बेंगलूरु, हैदराबाद, नई दिल्ली और मुंबई, 4 मार्च

देश में 28 लोगों के कोरोनावायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद आज कंपनी जगत ने इस संकट से निपटने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। हालांकि, कई कंपनियों के कर्मचारी इससे दहशत में नजर आए।

हैदराबाद में रहेजा माइंडस्पेस आईटी पार्क में एक महिला कर्मचारी में कोरोनावायरस के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद वहां स्थित कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर्मचारियों को उनके दफ्तरों से निकाला गया। इस खबर के फैलते ही वहां हड़कंप मच गया था। तेलंगाना में यह कोरोनावायरस के संक्रमण दूसरा मामला है। संक्रमित महिला डच कंपनी डीएसएम शेयर्ड सर्विसेज की कर्मचारी है जो हाल में इटली से लौटी है। कंपनी ने कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में महिला कर्मचारी के कोरोनावायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की। कंपनी ने कहा कि महिला कर्मचारी का अस्पताल में अलग वार्ड में इलाज चल रहा है। डीएसएम, डफ ऐंड फेल्प्स और कुछ अन्य कंपनियों के कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया। इन सभी कंपनियों के दफ्तर माइंडस्पेस आईटी पार्क में हैं।

इसी तरह अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर प्रॉडक्ट आईटी कंपनी ने बेंगलूरु के मान्यता टेक पार्क में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को शुक्रवार तक घर से काम करने को कहा है। कंपनी के एक अधिकारी में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दिए। यह अधिकारी हाल में कोरोनावायरस से प्रभावित देश से होकर आया है। हालांकि डॉक्टरों ने इस अधिकारी को कोरोनावायरस से मुक्त करार दिया है लेकिन कंपन ने एहतियात के तौर पर अपने परिसर में दवा का छिड़काव शुरू कर दिया है।

ऑनलाइन रिटेलर एमेजॉन ने अपने सिएटल ऑफिस में कोरोनावायरस के पहले मामले की पुष्टि की है। कंपनी की भारतीय इकाई ने अपने कर्मचारियों को एहतियात बरतने और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने को कहा है। कंपनी ने कहा कि एमेजॉन इंडिया के सभी कर्मचारियों को देश में कहीं भी जाने से पहले अपने मैनेजर से सलाह मशविरा करना होगा जबकि विदेश जाने के लिए वाइस-प्रेजिडेंट से मंजूरी जरूरी होगी।

वॉलमार्ट के मालिकाना हक वाली दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भी अपने कर्मचारियों को कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाने के लिए उनके देश-विदेश के व्यावसायिक दौरे पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। कंपनी ने एक आंतरिक सर्कुलर में कहा कि बेहद जरूरी होने पर उन्हें मुख्य कार्याधिकारी कल्याण कृष्णमूर्ति या सीनियर वाइस प्रेजिडेंट की अनुमति लेनी होगी। कर्मचारियों को सुझाव दिया गया है कि फ्लू जैसे लक्षण होने पर वे घर से काम करें। कंपनी ने प्रवक्ता ने कहा, 'हम मीटिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही एहतियात के तौर पर ऐसे कार्यक्रमों से परहेज किया जा रहा है जहां भारी संख्या में लोग जुटते हैं।' टेक महिन्द्रा और आईपीई ग्लोबल जैसी कंपनियों ने भी कई आयोजन रद्द कर दिए हैं।

इस बीच कर्नाटक सरकार ने आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को परामर्श जारी कर कोरोनावायरस से प्रभावित देशों की गैर जरूरी यात्रा से बचने और चीन, कोरिया, इटली, जापान तथा ईरान की यात्रा से परहेज करने को कहा है। विप्रो और टीसीएस जैसी आईटी सेवा प्रदाता कंपनियां पहले ही अपने कर्मचारियों को अंतरराष्ट्रीय यात्राओं से दूर रहने का सुझाव दे चुकी हैं।

(शेष पृष्ठ 14 पर)

...हरकत में सरकार

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा देश में कोरोनावायरस के 28 मामलों की हुई है पुष्टि
- कोरोना के लक्षणों का पता लगाने के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की होगी जांच
- केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री हर दिन रख रहे स्थिति पर नजर
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा किसी होली मिलन कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल
- विदेश मंत्रालय ने कहा कि 17 भारतीय विदेश में हैं कोरोना से संक्रमित
- दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्थिति से निपटने के लिए कार्यबल का किया गठन

10 बैंकों के विलय को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विलय योजना को दी हरी झंडी, 1 अप्रैल से प्रभावी होगा एकीकरण

सोमेश झा
नई दिल्ली, 4 मार्च

केंद्र सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर चार बैंक बनाने की योजना को आज मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर एकीकरण योजना के अनुसार बैंकों का यह विलय 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और उस समय इन बैंकों की बैलेंस शीट और शेयरों का एकीकरण किया जाएगा। पंजाब नैशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मिलकर देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनेगा। इसी तरह केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आन्ध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय होगा। इसके अलावा इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का विलय होगा।

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'विलय से इन बैंकों की उधारी क्षमता बढ़ने से कारोबार और उद्योग को फायदा होगा और व्यक्तिगत कर्जदार की नियामकीय सीमा 1,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,000 करोड़ रुपये हो जाएगी।' उन्होंने कहा कि बैंक विशेषीकृत ऋण उत्पाद पेश करने में भी सक्षम होंगे। बैंक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तत्काल काम करेंगे। पहला कदम शेयरों की अदला-बदली अनुपात को मंजूरी देने की होगी और इसके लिए एंकर बैंक के साथ बोर्ड बैठक आयोजित की जाएगी। पंजाब नैशनल बैंक की बोर्ड बैठक गुरुवार को प्रस्तावित है। बैंक अल्पांश शेयरधारकों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र समिति का भी गठन करेंगे। हालांकि देना बैंक और विजया बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय के दौरान शेयरधारकों से प्रतिक्रिया मंगाने के लिए जितना समय दिया गया था, इस बार यह समयसीमा कम हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 10 सार्वजनिक बैंकों के विलय पर निर्णय लेने से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के एकीकरण के लाभों का आकलन करना चाह रही थी। (शेष पृष्ठ 4 पर)

विलय के मायने

बैंक कर्मचारियों के लिए : कोई छंटनी नहीं होगी, बैंक कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों के लिए सर्वश्रेष्ठ दृष्टिकोण अपनाएंगे। बैंक अधिकारियों की पदोन्नति उचित अनुपात में होगा।

ग्राहकों के लिए : अकाउंट नंबर समान रहेगा। ग्राहकों को कुछ समय तक मौजूदा डेबिट कार्ड और चेक बुक रखने की अनुमति होगी। सेवा शुल्क एकीकृत बैंकों में जिसका सबसे कम होगा, उसे रखा जाएगा। ऋण प्रक्रिया में तेजी आएगी।

कारोबार के लिए : बड़े ऋण लेने की सुविधा होगी। विशेषीकृत ऋण उत्पाद को सपोर्ट करने में सक्षम होंगे।

कंपनी संशोधन विधेयक को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 में 72 बदलावों को मंजूरी दे दी। इनमें छोटी-मोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी से हटाने और 'ब्रांड भारत' को मजबूत करने के लिए घरेलू कंपनियों को विदेश में सूचीबद्ध होने की मंजूरी देने पर जोर दिया गया है। कंपनी संशोधन विधेयक को संसद के चालू सत्र में पेश किया जा सकता है। पृष्ठ 4

एयर इंडिया में 100 फीसदी हिस्सा ले सकेंगे एनआरआई

एयर इंडिया के निजीकरण में निवेशकों की रुचि बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को विमानन कंपनी में 100 फीसदी हिस्सेदारी देने की अनुमति दे दी है। एक छोटे से बदलाव से एयर इंडिया में विदेशी निवेश के नियमों को अन्य निजी विमानन कंपनियों के बराबर कर दिया गया है। पृष्ठ 4

क्रिप्टो पर आरबीआई का परिपत्र खारिज

राजेश भयानी और अनूप रॉय
मुंबई, 4 मार्च

- 50 लाख भारतीय कर रहे थे आभासी मुद्रा में लेनदेन
- अप्रैल 2018 तक एक्सचेंजों पर 100 करोड़ रुपये का हुआ था कारोबार
- सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की बाजार पूंजी है 159 अरब डॉलर
- अदालत के फैसले से एक्सचेंजो को मिलेगी राहत

उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व बैंक के अप्रैल 2018 के उस परिपत्र को आज खारिज कर दिया जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो करेंसी से दूर रहने को कहा गया था। न्यायालय ने कहा कि उसने अनुपात के आधार पर इस परिपत्र को खारिज किया है। इससे क्रिप्टो करेंसी का लेनदेन करने वाले एक्सचेंजों को राहत मिली है और अब देश में आभासी मुद्राओं के बाजार का मार्ग प्रशस्त होगा।

न्यायालय ने 180 पन्नों के अपने फैसले में एक तरह से क्रिप्टो परिसंपत्तियों और देश में इस तरह की सेवाएं देने वाले एक्सचेंजों में कारोबार और निवेश की अनुमति दे दी है। क्रिप्टो करेंसी मूल्य का डिजिटल प्रारूप होती हैं जिनका डिजिटल तरीके से कारोबार हो सकता है और ये लेनदेन के माध्यम या खाते की इकाई या मूल्य के भंडारण के रूप में काम कर सकती हैं। हालांकि इसे कानूनी रूप से मुद्रा का दर्जा हासिल नहीं है।

टैक्समैन के डीजीएम रचित शर्मा ने कहा, 'न्यायालय का फैसला निवेशकों और मध्यस्थों के लिए एक अस्थायी राहत हो सकता है। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित करने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है। इसमें सरकार द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी को छोड़कर इस तरह की सभी मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। तब तक सभी मध्यस्थों और बैंकों को भारत में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने की पूरी छूट है।'

न्यायालय के इस फैसले से ब्लॉकचेन को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। इस मामले में द इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) का पक्ष रखने वाली फर्म निशीथ देसाई एसोसिएट्स के संस्थापक निशीथ देसाई ने कहा, 'हम 2013 से इन पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस बारे में सरकार को स्वनियमन का मसौदा सौंप चुके हैं जिसमें क्रिप्टो कारोबार और केवाईसी नियमों के सर्वश्रेष्ठ नियमों को शामिल किया गया है। इस फैसले से भूमि रिकॉर्ड, ई-वोटिंग, स्टॉक रिकॉर्ड आदि मामलों में ई-गवर्नेंस के फायदे के लिए ब्लॉकचेन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। इससे सरकार को भी फायदा होगा क्योंकि उसे ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मिलेगा।'

एक्सचेंज क्रिप्टो में कारोबार शुरू करने को बेताब हैं। अभी कई एक्सचेंज सिंगापुर, माल्टा या मलेशिया से काम कर रहे हैं। वे वहां से भारतीय निवेशकों को सेवाएं दे रहे हैं। बड़े एक्सचेंजों में शामिल जेबपे के प्रवर्तकों ने हाल में अपनी हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों को बेच दी थी। न्यायालय के आज के फैसले के बाद जेबपे और अन्य एक्सचेंजों को क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की खरीदफरोख्त की अनुमति दी जा सकती है। कानूनी जानकार और खेतान ऐंड कंपनी में पार्टनर अभिषेक ए रस्तोगी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से उन निवशकों और एक्सचेंजों की समस्या दूर होगी जिन्हें अपना कारोबार भारत से ले जाना पड़ा था।

आरबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि बैंक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से पहले विस्तार से न्यायालय के फैसले का अध्ययन करेगा। ***(साथ में अरूप रायचौधरी)***

मास्क की कालाबाजारी पर रोक लगाएगी दिल्ली सरकार

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 4 मार्च

- **60** से **70** रुपये वाला एन-95 मास्क **180** से **250** रुपये में बिक रहा है
- सरकार करेगी कालाबाजारी की जांच, दोषियों पर कार्रवाई

दिल्ली में कोरोनावायरस का मामला सामने आने के बाद मास्क की मांग अचानक बढ़ने से इसके दाम भी दो से तीन गुना बढ़ चुके हैं। कारोबारी दाम बढ़ने की वजह बाजार में मास्क की किल्लत होना बता रहे हैं लेकिन कीमतों में अचानक इतनी वृद्धि के पीछे कालाबाजारी को लेकर भी संदेह हो रहा है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार मास्क की जमाखोरी के खिलाफ सख्ती की तैयारी कर रही है। दिल्ली के भागीरथ प्लेस के थोक दवा बाजार में दिसंबर में 60 से 70 रुपये और जनवरी-फरवरी में 100 से 120 रुपये में बिकने वाला एन-95 मास्क अब 180 से 250 रुपये में बिक रहा है। स्थानीय बाजारों में इसके दाम 300 रुपये से भी ऊपर चले गए हैं।

मास्क के दाम में बेहताशा वृद्धि पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार इसकी जांच कराएगी और कालाबाजारी रोकने के उपाय करेगी। ऑल इंडिया केमिस्ट ऐंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष कैलाश गुप्ता ने कहा कि मास्क की मांग बढ़ने से बाजार में इनकी कमी है, जिससे दाम बढ़ गए हैं। भागीरथ प्लेस के मास्क कारोबारी अमित कहते हैं कि पहले चीन से भी मास्क आ रहे थे लेकिन अब आयात ठप है। ऐसे में अब मास्क की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। हालांकि बाजार में मास्क की किल्लत नहीं है।

50 हजार तक पहुंचने को बेताब सोना

राजेश भयानी
मुंबई, 4 मार्च

- अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर घटाने से सोने की कीमतों में आई तेजी
- सोने का बाजार चक्र **8** से **10** साल का है और तेजी का चक्र अभी शुरू हुआ है
- मुंबई के हाजिर बाजार में **43,130** रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंचा सोना

सोने की कीमतों में आज अचानक तेजी दर्ज की गई। सोने के भाव में एक दिन में लगभग 1,000 रुपये तक की तेजी आई जिससे इसके 50,000 रुपये (प्रति 10 ग्राम) के आंकड़े पर पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है।

मुंबई के बाजार में सोने का दाम करीब 1,000 रुपये चढ़कर 43,130 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत की अचानक कटौती किए जाने की घोषणा के बाद यहां सोने के भाव में यह तेजी देखने को मिली है। अमेरिकी फेडरल ने मंगलवार की शाम अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मुहैया कराने के प्रयास में ब्याज दर में कटौती का निर्णय लिया।

हालांकि और ज्यादा तेजी की उम्मीद कर रहे विश्लेषकों का कहना है कि उस स्तर (50,000 रुपये) तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रह सकता है, लेकिन कोरोनावायरस की मौजूदा महामारी की वजह से ऐसा संभव हो सकता है।

विश्लेषकों का कहना है कि चूंकि कोरोनावायरस तेजी से फैल रहा है और यह बड़े जोखिम के तौर पर तब्दील हो रहा है, जिससे सोने की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। इस धातु को 50 हजारी (प्रति 10 ग्राम) बनने के लिए 16 प्रतिशत तेजी की जरूरत है। वर्ष 2020 में भारत में अब तक सोने की कीमत में 10 प्रतिशत का इजाफा पहले ही दर्ज किया जा चुका है। वर्ष 2019 से सोना 30 प्रतिशत चढ़ चुका है। बाजार विश्लेषकों को मौजूदा भाव से सोने में 16 प्रतिशत की और तेजी आने की संभावना है। हालांकि इसके लिए इस धातु को अपनी पिछली सभी ऊंचाइयों को पार करना होगा। सोने ने वर्ष 2011 में 1900 डॉलर की सर्वाधिक ऊंचाई को दर्ज किया था। अरोड़ा रिपोर्ट के एल्गो विशेषज्ञ लेखक के तौर पर चर्चित निगम अरोड़ा ने कहा, 'यदि कोरोनावायरस को लेकर स्थिति और बदतर होती है, केंद्रीय बैंक आक्रामक तौर पर कदम उठाते हैं और शेयर बाजार में गिरावट आती है तो सोना वर्ष के अंत तक 1900 डॉलर पर पहुंच सकता है।'

सोने की 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम कीमत का मतलब है कि दो वर्षों की अवधि में सोने में कीमत प्रतिफल 60 प्रतिशत से ज्यादा रहना। क्या यह उस ऊंचाई पर पहुंच सकता है? कुबेरा डॉटइन के मुख्य कार्याधिकारी गौरव रस्तोगी कहते हैं, 'सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के पिछले कई दशकों में हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि सोने का बाजार चक्र 8-10 साल का है। आठ साल के अंतराल के बाद सोने ने तेजी के चक्र में प्रवेश किया है।'

(शेष पृष्ठ 6 पर)

खबरों में रहे स्टॉक

सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज

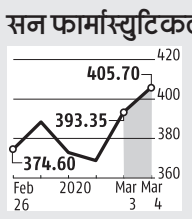

प्रवर्तक समूह सांघवी फाइनैंस ने खुले बाजार से खरीदे 19.8 लाख शेयर

₹ 393.35 पिछला बंद भाव
₹ 405.70 आज का बंद भाव
▲ 3.14 %

स्पाइसजेट

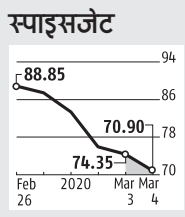

कोरोनावायरस की चिंता से विमानन शेयरों पर दबाव

₹ 74.35 पिछला बंद भाव
₹ 70.90 आज का बंद भाव
▼ 4.64 %

इंडसइंड बैंक

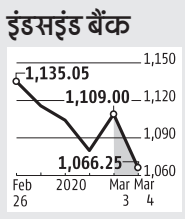

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर

₹ 1,109.00 पिछला बंद भाव
₹ 1,066.25 आज का बंद भाव
▼ 3.85 %

स्टर्लिंग ऐंड विल्सन सोलर

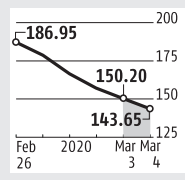

एक महीने में 51 फीसदी टूटा शेयर

₹ 150.20 पिछला बंद भाव
₹ 143.65 आज का बंद भाव
▼ 4.36 %

एशियन पेंट्स

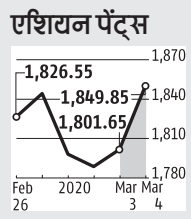

कच्चे माल के दाम घटने से मार्जिन में सुधार की उम्मीद

₹ 1,801.65 पिछला बंद भाव
₹ 1,849.85 आज का बंद भाव
▲ 2.67 %

संक्षेप में

एचडीएफसी बैंक ने खोज समिति में किया बदलाव

एचडीएफसी बैंक ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी आदित्य पुरी का उत्तराधिकारी खोजने के लिए गठित खोज समिति का पुनर्गठन किया है। निजी क्षेत्र के इस ऋणदाता ने बुधवार को शेयर बाजारों को इस बारे में जानकारी दी। इस खोज समिति में केकी मिस्त्री के स्थान पर रेणु कर्नाड को रखा गया है। कर्नाड बैंक की मूल कंपनी एचडीएफसी से जुड़ी हैं। मिस्त्री बतौर निदेशक लगातार आठ साल पूरे करने के बाद निदेशक मंडल से हट गए हैं। नियमों के तहत कार्यकाल की यह अधिकतम अवधि है। पुरी 26 अक्टूबर 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। *बीएस*

350 करोड़ रुपये के एनसीडी को मंजूरी

बिजली उत्पादक व वितरक सीईएससी लिमिटेड ने गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (एनसीडी) के जरिये कई चरणों में 350 करोड़ रुपये जुटाने का फैसला लिया है। 120 करोड़ रुपये की एनसीडी का पहला चरण फरवरी 2021-24 में देय होगा। सूत्रों ने कहा कि इससे जुटाई गई रकम का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च पर होगा। *बीएस*

माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेंचर ने किया समझौता

माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेंचर ने बुधवार को कहा कि उन्होंने सामजिक क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों और स्टार्ट-अप की मदद के लिए समझौता किया है। दोनों कंपनियों ने कहा कि इस संयुक्त पहल के माध्यम से सामाजिक उद्यमों को समर्थन और प्रौद्योगिकी मुहैया कराई जाएगी, ताकि उन्हें समाधान और बिजनेस मॉडल बनाने में मदद मिले जिससे दुनिया भर में अधिक से अधिक लोगों को ज्यादा ठोस और स्थाई लाभ मिल सके। *भाषा*

नई गैस परिवहन कंपनी गेल की होगी

मंत्रिमंडल इस मुद्दे पर जल्द लेगा फैसला, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बरकरार रहेगी

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 4 मार्च

सरकार जल्द ही एक अलग गैस परिवहन कंपनी बना सकती है जिसके पास गेल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलान परिसंपत्तियां होंगी। नई कंपनी गेल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई होगी।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई गैस पारेषण कंपनी सृजित करने के लिए इंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के लिए एक कैबिनेट नोट पहले ही जारी कर चुका है। इस मामले के करीबी एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, 'योजना के अनुसार, इंडियन ऑयल की मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए गेल बुक वैल्यू का भुगतान करेगी। उसे गेल की प्रस्तावित सहायक इकाई के साथ एकीकृत करने की योजना है।' अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इंडियन ऑयल की पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को गेल की प्रस्तावित सहायक इकाई में शामिल नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी दे सकता है।

उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की निर्माण लागत करीब 3 से 3.5 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर होगी। इसका मतलब साफ है कि इंडियन ऑयल की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खरीदने के लिए गेल को करीब 500 से 600 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ेगा।

फिलहाल देश में कुल 16,981 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता है जिसकी रोजना परिवहन क्षमता 38.7 करोड़ मिट्रिक घन मीटर है। इसके अलावा गेल के पास 12,160 किलोमीटर और इंडियन ऑयल के पास करीब 162 किलोमीटर गैस पाइपलाइन है।

गेल के चेयमैन एवं प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने फरवरी में कहा था कि सरकार नियमों का अनुपालन करने के क्रम में गेल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। नियमों के तहत गैस के परिवहन और विपणन कारोबार को अलग करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी की स्थापना एक साल के भीतर हो जाएगी जो मंत्रिमंडल की मंजूरी पर निर्भर करेगी।

गेल के राजस्व में प्रस्तावित इकाई की हिस्सेदारी करीब 15 फीसदी होगी। इंडियन ऑयल 140 किलोमीटर लंबी दादरी-पानीपत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (डीपीपीएल) का परिचालन करती है। इस पाइपलाइन को 2010 में चालू किया गया था जो गेल की हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन (एचवीजेपीएल) और दहेज विजयपुर पाइपलाइन (डीवीपीएल) को दादरी में जोड़ती है।

इंडियन ऑयल की शेष 22 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन एन्नोर ओर मलाली को जोड़ती है जहां इंडियन ऑयल की सहायक इकाई चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (सीपीसीएल) की रिफाइनरी है।

प्रस्तावित सहायक इकाई संबंधी योजना के बारे में पूछे जाने पर गेल के एक अधिकारी ने कहा, 'प्राकृतिक गैस ग्रिड तैयार करने की तत्काल जरूरत है। साथ ही बढ़ती मांग के अनुरूप आपूर्ति को भी दुरुस्त किया जाना चाहिए। इसलिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली विशेष सहायक इकाई स्थापित होने से पारेषण क्षेत्र की कुशलता बेहतर होगी और कारोबार में कहीं अधिक पारदर्शिता आएगी।'

इंडियन ऑयल और गेल के अलावा अन्य जिन कंपनियों के पास प्राकृतिक गैस पाइपलाइन मौजूद है उनमें गुजरात स्टेट पेट्रोनेट (जीएसपीएल), रिलायंस ऐंड असम रीजनल नेटवर्क (एआरएन) शामिल है।

गैस परिवहन के लिए ग्रिड की तैयारी

- नई कंपनी गेल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई होगी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी दे सकता है
- इंडियन ऑयल की मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए गेल बुक वैल्यू का भुगतान करेगी

संपन्न ग्राहकों के लिए नए उत्पाद लाएगी कोका कोला

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 4 मार्च

कोका कोला की भारतीय शाखा खास तौर पर संपन्न और महत्त्वाकांक्षी उपभोक्ता वर्ग में विभिन्न उत्पाद और ब्रांड लाने की योजना बना रही है। कंपनी का मानना है कि इससे देश में उसके मुनाफे में इजाफे को मदद मिलेगी।

कंपनी ने देश में अपने उपभोक्ता आधार को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया है। संपन्न वर्ग, जो अधिक दाम वहन कर सकते हैं और जिनसे कंपनी को बेहतर लाभ हो सकता है, मध्य स्तरीय खंड, जो मुख्य रूप से उसके मौजूदा उत्पादों के खरीदार हैं तथा महत्त्वाकांक्षी उपभोक्ता, जो अपने बजट के अनुकूल पेय के विकल्प चुनते हैं।

कोका कोला के अनुसार मूल्य निर्धारण के हिसाब से किफायती खंड 10 से 15 रुपये के बीच, मध्य स्तरीय खंड 15 से 20 रुपये तथा 25 रुपये से अधिक वाला कोई भी उत्पाद संपन्न खंड के लिए है। उपभोक्ता आधार के लिहाज से अमेरिका स्थित इस बहु-राष्ट्रीय कंपनी का मानना है कि देश में लगभग पांच से छह करोड़ लोग इस संपन्न वर्ग में आएंगे जिसके बाद करीब 45-50 करोड़ लोग मध्य स्तरीय उपभोक्ता होंगे। बाकी लगभग 85 करोड़ की आबादी में महत्त्वाकांक्षी वर्ग में शामिल है।

कोका कोला इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया के अध्यक्ष टी कृष्णकुमार ने कहा कि अपने मौजूदा पोर्टफोलियो के साथ मध्य स्तरीय वर्ग में हमारी अच्छी पैठ है। संपन्न और महत्त्वाकांक्षी वर्ग में हमें और उत्पादों की जरूरत है।

इस प्रयास के तहत कोका कोला ने पहले ही स्मार्टवाटर के साथ-साथ श्वेप्स पेश किया है जिसमें संपन्न उपभोक्ताओं को लक्ष्य बनाया गया है। इसने रानी फलोट भी पेश किया है।

कृष्णकुमार ने कहा कि नए उत्पाद लाने के तहत स्मार्टवाटर और श्वेप्स के पोर्टफोलियो में विस्तार किया जाएगा तथा खातिरदारी के खंड में और जूस उत्पादों पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल भारत में इसके 65 उत्पाद हैं।

कोका कोला का मानना है कि सभी उपभोक्ता मूल्य स्तरों के नए उत्पादों से भारत को वैश्विक स्तर पर उसका तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनाने का लक्ष्य पूरा होगा।

फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच का आदेश

भाषा
नई दिल्ली, 4 मार्च

नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने बुधवार को उचित व्यापार व्यवहार क्षेत्र के नियामक सीसीआई से कहा कि वह फ्लिपकार्ट के खिलाफ कथित रूप से अपनी प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर जांच शुरू करे। एनसीएलएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पीठ ने इस संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के पिछले आदेश पर रोक लगा दी। इससे पहले सीसीआई ने अपने पिछले आदेश में ई-कॉमर्स क्षेत्र की बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट को उसकी प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया था। अपील न्यायाधिकरण ने सीसीआई को निर्देश दिया कि वह अपने महानिदेशक से आरोपों की जांच करने के लिए कहे।

पीठ ने कहा कि उचित व्यवहार नियामक को फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया जाता है। एनसीएलएटी ने कहा कि अखिल भारतीय विक्रेता संघ (एआईओवीए) ने अपना पक्ष अच्छी तरह रखा है। सीसीआई ने छह नवंबर 2018 को आदेश जारी करते हुए कहा था कि फ्लिपकार्ट और एमेजॉन ने प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग के एआईओवीए के आरोपों को खारिज कर दिया था।

वोडा आइडिया बंद हुई तो टावर को थोड़ा झटका

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 4 मार्च

वोडाफोन आइडिया का परिचालन बंद होने की सूरत में मोबाइल टावर कंपनियों को तगड़ा झटका लगेगा। टावर कंपनियों को एक ऐसा किरायेदार खोना पड़ेगा जो उनके करीब एक तिहाई टावरों का इस्तेमाल करती है। इससे टावर कंपनियों के किराया अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आएगी और राजस्व एवं मुनाफे के मोर्चे पर उन्हें जबरदस्त नुकसान होगा। विभिन्न आकलन के अनुसार, टावर कंपनियों को इससे करीब 8,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का नुकसान होगा।

हालांकि टावर कंपनियों का कहना है कि लघु अवधि की यह समस्या तीन साल के भीतर खत्म हो जाएगी क्योंकि डेटा की उपयोगिता बढ़ रही है और 5जी सेवाएं शुरू होने से कहीं अधिक टावर क्षमता की जरूरत होगी। तमाम आकलन के अनुसार, वोडाफोन आइडिया विभिन्न वेंडरों के 1,80,000 टावरों (48 लाख सक्रिय टावरों में) का इस्तेमाल करती है।

अधिकतर बड़ी कंपनियों के मामले में औसत किराया फिलहाल 1.7 से 1.8 और एक भी किरायेदार के खोने से उनके राजस्व, मार्जिन और व्यवहार्यता पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा। इससे उनके किराये में गिरावट का चलन बढ़ेगा।

ऑप्टिकल फाइबर सहित दूरसंचार उपकरण विनिर्माताओं का कहना है कि यदि वोडाफोन आइडिया का परिचालन बंद हुआ तो वित्त वर्ष 2020 में करीब 1.7 अरब डॉलर के ऑर्डर का नुकसान होगा। इससे एरिक्सन, नोकिया और हुआवे जैसी प्रमुख कंपनियों को झटका लगेगा क्योंकि इन सभी कंपनियों ने वोडाफाने आइडिया के साथ अनुबंध किए हैं।

हालांकि दूरसंचार टावरों का संचालन करने वाली कंपनियां कई कारणों से अच्छे समय की उम्मीद कर रही हैं। उनका कहना है कि यदि वोडाफोन आइडिया नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) का रुख करेगी तो उसका समाधान पेशेवर आश्वस्त करेगा कि कंपनी का परिचालन जारी रहे।

एक टावर कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) ने कहा, 'एयरसेल के अनुभव (जो एनसीएलटी में है) से लोगों को पता चल चुका है कि यदि परिचालन बंद हुआ तो परिसंपत्ति मूल्य में नाटकीय गिरावट आएगी।' उन्होंने कहा कि कंपनी टावरों की संख्या में 50 से 60 हजार की कमी कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि वोडाफोन आइडिया के मामले में ग्राहकों की संख्या 30 करोड़ से अधिक है और प्रतिस्पर्धी ऑपरेटरों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वे उन सभी ग्राहकों को अपने नेटवर्क पर पोर्ट करा लें।

सीईओ ने कहा, 'हमारा मानना है कि वोडाफोन आइडिया को कोई भी खरीदे अथवा यदि उसकी परिसंपत्तियों को भुनाए तो उनके पास विकल्प सीमित होगा। नए मालिक को अपने ग्राहकों के लिए करीब दो लाख टावरों का किराया जारी रखना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धी दूरसंचार ऑपरेटर चाहते हुए भी इतनी बड़ी तादाद में ग्राहकों को अपने नेटवर्क पर नहीं ले पाएंगे। कुल मिलाकर उनके नेटवर्क की 65 फीसदी औसत क्षमता पहले से ही भरी हुई है और व्यस्त समय में यह आंकड़ा 95 फीसदी तक पहुंच जाता है। इसलिए उन्हें किराये पर अधिक टावर लेने की जरूरत होगी।'

दूरसंचार ऑपरेटरों ने उम्मीद जताई है कि अगले तीन वर्षों में डेटा की औसत उपयोगिता दोगुना होकर 20 जीबीपीएस प्रति ग्राहक प्रति महीना हो जाएगा। इसे हासिल करने के लिए उन्हें टावर बुनियादी ढांचा और नए कारोबार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगले तीन वर्षों में 5जी सेवाओं का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। इससे ऑपरेटरों को हाई स्पीड इंटरनेट बरकरार रखने के लिए टावरों की संख्या को तिगुना करने की जरूरत होगी।

बहरहाल, वोडाफोन आइडिया का भविष्य इंडस टावर्स (वोडाफोन पीएलसी, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल का संयुक्त उपक्रम) और भारती इन्फ्राटेल के प्रस्तावित विलय की राह में एक बड़ी बाधा है। विलय में एक बार फिर दो महीने की देरी हो गई है।

अग्रणी टावर कंपनियां

टावरों की संख्या

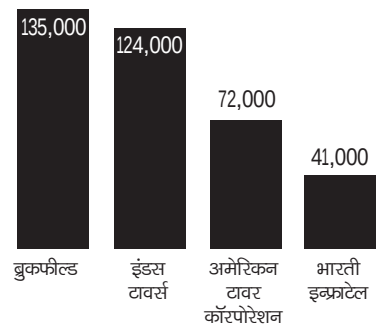

रिलायंस इन्फ्राटेल के पास करीब 43,000 टावर मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल जियो कर रही है। कुछ छोटी कंपनियां भी मौजूद हैं। *स्रोतः कंपनी और उद्योग के आकलन*

ऋण चुनौतियों से निपट लेगी मैक्रोटेक

मैक्रोटेक डेवलपर्स (पूर्व में लोढ़ा डेवलपर्स) अपने प्रस्तावित बॉन्ड के जरिये निकट भविष्य की ऋण समस्याओं को दूर कर सकती है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने अपनी एक रिपोर्ट में यह भी कहा है कि ऋण परिपक्वता और उद्योग परिदृश्य अनुकूल न होने के कारण पुनर्वित्त के लिए जोखिम बरकरार रहेगा। साथ ही नकदी प्रवाह की स्थिति भी कमजोर बनी रहेगी। मूडीज की विश्लेषक श्वेता पटोदिया ने कहा, 'प्रस्तावित बॉन्ड उल्लेखनीय निष्पादन और बाजार जोखिम पर निर्भर करेगा जिसमें बॉन्ड की शर्तों को पूरा करना भी शामिल है। इससे योजना के अनुसार बॉन्ड का लेनदेन पूरा करने संबंधी मैक्रोटेक डेवलपर्स की क्षमता को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है।' *बीएस*

मझोली आईटी कंपनियों का बेहतर प्रदर्शन!

देवाशिष महापात्र
बेंगलूरु, 4 मार्च

एलऐंडटी इन्फोटेक (एलटीआई), एमफैसिस, माइंडट्री और एलऐंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसी मझोली आईटी सेवा कंपनियों का प्रदर्शन आगामी तिमाहियों में बड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनियों के मुकाबले बेहतर रहने के आसार हैं। उद्योग विश्लेषकों और ब्रोकरेज फर्मों ने यह अनुमान जाहिर किया है।

विश्लेषकों का कहना है कि टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज (टीसीएस), इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजिज और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों के मुकाबले मझोली कंपनियां ढांचागत तौर पर कहीं बेहतर स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी करने की योग्यता और दमदार नेतृत्व क्षमता जैसे कारकों के कारण मझोली आईटी कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन के आसार दिख रहे हैं।

एचएसबीसी की एक रिपोर्ट में योगेश अग्रवाल और विवेक गेडुा ने कहा, 'कुछ मिडकैप कंपनियों के लिए ढांचागत वृद्धि लार्जकैप कंपनियों के मुकाबले बेहतर हो सकती है। हमारा मानना है कि छोटी आईटी कंपनियांडिजिटल सौदे हासिल करने के कारण बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि उनका आकार छोटा लेकिन कारोबार का दायरा बड़ा है।'

बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी की योग्यता और दमदार नेतृत्व क्षमता के कारण मझोली आईटी कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन के आसार

रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े सौदे हासिल करने की राह में प्रमुख बाधा को इन मझोली कंपनियों ने प्रतिभाओं की नियुक्ति के जरिये पार कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'मिडकैप कंपनियों वृद्धि के निलए सबसे बड़ी चुनौती बड़े सौदे हासिल करने में अक्षमता रही है। अब उसमें बदलाव आ रहा है क्योंकि कई मझोली कंपनियां बड़ी कंपनियों से वरिष्ठ प्रतिभाओं की नियुक्तियां कर रही हैं।'

रिपोर्ट के अनुसार, 'मुझे लगता है कि बड़े सौदे के लिए बोली और उसका प्रबंधन इन कंपनियों के लिए एकमात्र बड़ा कारण है जिससे अगले कुछ वर्षों में राजस्व को लगातार रफ्तार मिलेगी।' उदाहरण के लिए, एलटीआई के मुख्य कार्याधिकारी संजय जालोन इन्फोसिस से आए हैं जहां वह हाईटेक एवं विनिर्माण इकाई के प्रमुख थे। इसी प्रकार, एलटीआई के मुख्य परिचालन अधिकारी नचिकेत देशपांडे इससे पहले कॉग्निजेंट में बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा) कारोबार के डिलिवरी प्रमुख थे।

माइंडट्री के मुख्य कार्याधिकारी और प्रबंध निदेशक देवाशिष चटर्जी भी इससे पहले कॉग्निजेंट में थे। एम्फैसिस के सीईओ एवं कार्यकारी निदेशक नितिन राकेश सिंटेल का नेतृत्व कर रहे थे। जबकि एनआईआईटी टेक्नोलॉजिज के सीईओ सुधीर सिंह नई दिल्ली की इस प्रौद्योगिकी कंपनी में आने से पहले जेनपैक्ट के एमडी (पूंजी बाजार) के तौर पर कार्यरत थे।

39 महीने के निचले स्तर पर 10 वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल

बाजार को दरों में कटौती का पूरा भरोसा पर आरबीआई के हाथ भी हैं बंधे हुए

अनूप रॉय
मुंबई, 4 मार्च

देश में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद में 10 वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल 12 आधार अंक फिसल गया क्योंकि वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने कोरोनावायरस के कारण आई आर्थिक मंदी को टालने के लिए मुख्य दरों में कटौती की है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्लूमबर्ग को मंगलवार को दिए साक्षात्कार में कहा था कि इस वायरस के कारण पैदा हुई मंदी से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक कुछ भी करने के लिए तैयार है।

दास ने कहा था, हम स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। निकट भविष्य में मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस या फोन के जरिये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चर्चा की उम्मीद कर रहा हूं। गवर्नर ने समाचार एजेंसी से कहा, भारत के मामले में दरों में कटौती और नकदी के कदमों के जरिये बाजार को सहारा देने का विकल्प है।

10 वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल 6.227 फीसदी पर बंद हुआ, जो 6 दिसंबर 2016 के बाद का निचला स्तर है, वहीं पांच वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल 14 आधार अंक टूट गया। इक्विटी सूचकांकों से संकेत लेते हुए भारतीय रुपया भी कारोबारी सत्र के निचले स्तर 73.64 से सुधरकर 73.23 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। आरबीआई मोटे तौर पर बाजार से दूर रहा, वहीं रुपये में ऑफशोर व ऑनशोर बाजारों के बीच आर्बिट्रेज का मौका कम हो गया।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने नीतिगत दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की है और इसने 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी नोट को पहली बार एक फीसदी से नीचे ला दिया।

अमेरिकी दरों में कटौती के बाद ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया ने भी नीतिगत दरों में कटौती की। दक्षिण कोरिया ने कोरोनावायरस के कारण आई मंदी से निपटने के लिए 9.8 अरब डॉलर के राहत पैकेज का ऐलान किया। हॉन्ग-कॉन्ग और सिंगापुर मांग बढ़ाने के लिए हेलिकॉप्टर से लोगों के बीच पैसे गिरा रही है।

अब बाजार को समझ में आ गया है कि दरों में कटौती होगी, संभवत: अगली मौद्रिक नीति समिति की अप्रैल में होने वाली बैठक से पहले। एमपीसी की बैठक जरूरी पड़ने पर हो सकती है।

आईडीबीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक और ट्रेजरी प्रमुक अशोक गौतम ने कहा, अब यह देखने की बात है कि दरों में कटौती कब होती है। आरबीआई विगत में पर्याप्त नकदी व क्रेडिट प्रवाह के लिए अपरंपरागत कदम उठा चुका है और उसके इच्छित नतीजे आने लगे हैं।

बार्कलेज के मुख्य अर्थशास्त्री (भारत) राहुल बाजोरिया के मुताबिक, निश्चित तौर पर उन कदमों का आर्थिक स्थिति को सहज बनाने में असर होगा, लेकिन क्रेडिट की कुल उपलब्धता पर उसके असर का अभी पता नहीं है।

बाजोरिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, सॉवरिन बॉन्ड का प्रतिफल घटा है, ऐसे में वैश्विक प्रतिफल में गिरावट के बीच कंपनियों को उधारी की लागत घटने की उम्मीद है।

आरबीआई अपना एलटीआरओ 1 लाख करोड़ रुपये की नियोजित सीमा के पार ले जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने एलटीआरओ में सिर्फ 25,000 करोड़ रुपये छोड़े हैं। गौतम ने कहा, उम्मीद है कि इसके और चरण होंगे।

बॉन्ड पर असर

- 10 वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल 6.227 फीसदी पर बंद हुआ, जो 6 दिसंबर 2016 के बाद का निचला स्तर है। पांच वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल 14 आधार अंक टूट गया
- इक्विटी सूचकांकों से संकेत लेते हुए भारतीय रुपया भी कारोबारी सत्र के निचले स्तर 73.64 से सुधरकर 73.23 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

फेड की कटौती से डेट एमएफ को होगा ज्यादा फायदा

जश कृपलानी
मुंबई, 4 मार्च

डेट म्युचुअल फंड के प्रबंधकों को उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज में कटौती का फायदा बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट के जरिए मिलेगा और बुधवार को 10 वर्षीय सरकाकरी प्रतिभूतियों का प्रतिफल 12 आधार अंक फिसलकर तीन साल के निचले स्तर 6.23 फीसदी पर आ गया।

मिरे एमएफ के प्रमुख (फिक्स्ड इनकम) महेंद्र जाजू ने कहा, बॉन्ड प्रतिफल में और कमी आ सकती है क्योंकि आरबीआई ने भी संकेत दिया है कि वह अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कदम उठाने को तैयार है।

बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि आरबीआई, अमेरिकी फेडरल रिजर्व से संकेत ले सकता है और देसी अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस के असर को कम करने के लिए ब्याज दरें घटाएगा।

बुधवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की क्योंकि कोरोनावायरस के प्रसार से अमेरिकी व वैश्विक

अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही थी। ब्याज दरों में कटौती से 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी का प्रतिफल अब तक के निचले स्तर 0.99 फीसदी पर आ गया। आदित्य बिड़ला सन लाइफ एमएफ के मुख्य निवेश अधिकारी (फिक्स्ड इनकम) मनीष डांगी ने कहा, हमें लगता है कि अप्रैल में आरबीआई ब्याज दरों में 25 से 50 आधार अंकों की कटौती करेगा। लंबी अवधि के बॉन्ड में तेजी की गुंजाइश बनी है।

कोटक एमएफ की मुख्य निवेश अधिकारी (फिक्स्ड इनकम) लक्ष्मी अय्यर ने कहा, ज्यादा संवेदनशीलता के कारण लंबी अवधि की प्रतिभूतियों में और फायदा मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर परिपक्वता वाली श्रेणियों को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की कटौती से फायदा मिल सकता है। इसके अलावा बॉन्ड बाजार आरबीआई की तरफ से ब्याज कटौती मानकर चल रहा है, हालांकि यह उम्मीद पूरी हो भी सकती है और नहीं भी।

अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आरबीआई पहले ही रीपो दरों में जनवरी से अब तक 135 आधार अंकों की कटौती कर चुका है। फंड मैनेजरों ने कहा कि 10 साल से कम अवधि वाली प्रतिभूतियां ज्यादा आकर्षक होंगी।

बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि गिल्ट फंड में और तेजी सीमित होगी क्योंकि ऐसे फंडों पर मजबूत आय पहले ही हासिल हो चुकी है। एक साल की अवधि, लंबी अवधि वाले फंडों में 17.4 फीसदी का लाभ हुआ है।

विशेषज्ञों ने कहा कि निवेशक 7-8 साल की परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों पर नजर डाल सकते हैं।

बाजार पर कोरोनावायरस के प्रभाव का आकलन कर रहा सेबी

भाषा
मुंबई, 4 मार्च

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) दुनिया के कई देशों में फैल चुके कोरोनावायरस के पूंजी बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव का आतंरिक तौर पर आकलन कर रहा है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य एस के मोहंती ने बुधवार को कहा, हालांकि वित्तीय क्षेत्र के नियामकों की शीर्ष संस्था वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद (एफएसडीसी) अभी इस विचार-विमर्श में शामिल नहीं हुई है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य की तरफ से यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब दुनियाभर में केंद्रीय बैंक हरकत में आ रहे हैं।

अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने मंगलवार को अचानक ब्याज दर में 0.5 फीसदी की कटौती कर सबको चौंका दिया। रिजर्व बैंक ने भी मंगलवार को बयान जारी कर बाजार को हरसंभव सहायता देने का भरोसा दिया है। मोहंती ने संवाददाताओं से कहा, सेबी कोरोनावायरस और इसके बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर जागरूक है। हम इस दिशा में जरूरी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने रिजर्व बैंक का बयान देखा है। हमें इसकी जानकारी है। जो कुछ भी किया जाना है वह किया जाना चाहिए। हम आंतरिक तौर पर स्थिति का आकलन कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि इस मुद्दे पर क्या एफएसडीसी में कोई चर्चा हुई है? जवाब में उन्होंने कहा, अभी नहीं। इससे पहले उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा पूंजी बाजार पर आयोजित एक सम्मेलन में मोहंती ने कहा कि सेबी ने रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) और इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) पर कराधान के विवादित मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाया है। वर्ष 2020- 21 के बजट में रीट और इनविट के लिए लाभांश वितरण कर (डीडीटी) में बदलाव का प्रावधान है।

एसबीआई काड्र्स आईपीओ को मिला संस्थागत निवेशकों का सहारा

बीएस संवाददाता
मुंबई, 4 मार्च

शेयर बाजार में उठापटक के बावजूद देश की दूसरी सबसे बड़ी कार्ड कंपनी एसबीआई काड्र्स ऐंड पेमेंट सर्विसेज के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को संस्थागत निवेशकों का सहारा मिला है।

तथाकथित पात्र संस्थागत खरीदार (क्यूआईबी) की श्रेणी में 57 गुना आवेदन मिले हैं और कुल बोली रिकॉर्ड एक लाख करोड़ रुपये के पार निकल गई है। क्यूआईबी श्रेणी में करीब आधी बोली विदेशी निवेशकों ने लगाई है। बुधवार को क्यूआईबी के लिए बोली का आखिरी दिन था। कुल मिलाकर आईपीओ को 15.2 गुना आवेदन मिले हैं। आईपीओ की अन्य श्रेणी में भी पेश किए गए शेयरों के मुकाबले ज्यादा मांग देखने को मिली है। बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि संस्थागत निवेशकों की भारी मांग अन्य निवेशकों (एचएनआई समेत) को आक्रामकता से बोली लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ज्यादातर ब्रोकरेज फर्मों ने अपने क्लाइंटों को एसबीआई काड्र्स के आईपीओ में आवेदन करने की सलाह दी है। इस आईपीओ का कीमत दायरा 750 से 755 रुपये प्रति शेयर है। कीमत दायरे के ऊपरी स्तर पर शेयर का मूल्यांकन 2019-20 के पहले नौ महीने की आय का 46 गुना बैठता है।

आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने एक नोट में कहा, एसबीआई कार्ड मजबूत लाभ वाले अद्भुत कारोबारी मॉडल में निवेश का मौका दे रहा है। उच्च कारोबारी बढ़त और रिटर्न का मजबूत अनुपात कारोबार के लिए प्रीमियम मूल्यांकन को सही ठहरा रहा है।

मजबूत मांग

संस्थागत निवेशकों की बोली 1 लाख करोड़ रुपये के पार

श्रेणी	आवेदन (गुना)
क्यूआईबी	57.2
एचएनआई	1.4
खुदरा	1.7
कर्मचारी	3.3
शेयरधारक	2.3
कुल	15.2

स्रोत : एनएसई, बीएसई
नोट : क्यूआईबी श्रेणी के लिए आवेदन की तारीख समाप्त

एसबीआई कार्ड का आईपीओ कोल इंडिया (15,200 करोड़ रुपये), रिलायंस पावर (11,700 करोड़ रुपये) और जीआईसी आरई (11,373 करोड़ रुपये) के बाद चौथा सबसे बड़ा निर्गम है। एसबीआई कार्ड के आईपीओ का आकार 10,300 करोड़ रुपये का है और कंपनी पहले ही एंकर निवेशकों को 2,800 करोड़ रुपये के शेयर आवंटित कर चुकी है। आईपीओ के जरिये एसबीआई कार्ड नए शेयर के जरिए 500 करोड़ रुपये जुटा रही है ताकि पूंजी का आधार मजबूत बना सके। बाकी 9,800 करोड़ रुपये के शेयर एसबीआई और पीई फर्म कार्लाइल बेच रहे हैं।

गति के लिए अलकार्गो को खुली पेशकश की अनुमति

अदिति दिवेकर
मुंबई, 4 मार्च

एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स कंपनी गति लिमिटेड में नियंत्रक हिस्सेदार बनने के तीसरे व आखिरी चरण में अलकार्गो लॉजिस्टिक्स ने आज कहा कि उसे गति के करीब 3.17 करोड़ शेयर यानी 26 फीसदी हिस्सेदारी 75 रुपये प्रति शेयर पर अधिग्रहीत करने के लिए खुली पेशकश लाने की मंजूरी सेबी से मिल गई है।

खुली पेशकश की पूरी स्वीकार्यता के बाद अलकार्गो की गति में हिस्सेदारी 46.83 फीसदी हो जाएगी और इस तरह से अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसकी शुरुआत 5 दिसंबर 2019 को हुई थी। बीएसई पर गति का शेयर आज 66.55 रुपये पर बंद हुआ। इस बीच, अलकार्गो का शेयर 1 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 110.40 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी ने कहा, खुली पेशकश इस महीने आने की संभावना है और अप्रैल 2020 में यह बंद हो जाएगा।

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स फर्म अलकार्गो खुली पेशकश के लिए जरूरी 238 करोड़ रुपये पहले ही एस्क्रो खाते में जमा करा चुकी है, जो सेबी के नियम के तहत खुली पेशकश के लेनदेन के लिए जरूरी है। अलकार्गो ने तरजीही शेयर के आवंटन और गति में प्रवर्तक हिस्सेदारी की खरीद का पहला दो चरण अलकार्गो ने जनवरी में पूरा कर लिया था। इस प्रक्रिया के तहत अलकार्गो लॉजिस्टिक्स के दो निदेशक गति के बोर्ड में नियुक्त हुए हैं।

> खुली पेशकश की पूरी स्वीकार्यता के बाद अलकार्गो की गति में हिस्सेदारी 46.83 फीसदी हो जाएगी

अलकार्गो लॉजिस्टिक्स के चेयरमैन शशि किरण शेट्टी के हवाले से कहा गया है, यह अधिग्रहण देसी कारोबार में मजबूती की अलकार्गो लॉजिस्टिक्स की लंबी अवधि की रणनीति के मुताबिक है। अभी गति की मौजूदगी देश के 727 जिले में है। जब अलकार्गो गति में बहुलांश हिस्सेदारी लेने की कोशिश कर रही थी तब गति प्रवर्तक परिवार के बीच शेयरों के स्वामित्व को लेकर अदालती विवाद में उलझी हुई थी।

गति के प्रवर्तक महेंद्र अग्रवाल के बेटे और पत्नी ने उनके खिलाफ कंपनी में कथित कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था और बोर्ड के पुनर्गठन की मांग की थी। अग्रवाल परिवार के सदस्यों ने एनसीएलटी के हैदराबाद पीठ से संपर्क कर कंपनी की गतिविधियों में हस्तक्षेप की मांग की थी।

मोतीलाल पीई ने डायग्नोस्टिक्स कंपनी में किया निवेश

सोहिनी दास
मुंबई, 4 मार्च

मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी फंड 240 करोड़ रुपये का निवेश डायग्नोस्टिक सेवा कंपनी मोलबायो में कर रहा है, जिसने एक ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट का विकास और वाणिज्यिकरण किया है जो 11 संक्रामक बीमारियों की जांच कर सकता है। 43 बीमारियों की जांच पर काम चल रहा है, जिसमें कोरोनावायरस शामिल है।

मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी की तरफ से प्रबंधित इंडिया बिजनेस एक्सिलेंस फंड-3 गोवा की शोध आधारित डायग्नोस्टिक कंपनी मोलबायो में निवेश कर रहा है। अपनी सहायक बिगटेक लैब्स के साथ मोलबायो ने टूनैट नामक जांच का विकास व वाणिज्यिकरण किया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का पहला मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स प्लेटफॉर्म है जो पीसीआर तकनीक का इस्तेमाल करता है।

फर्म ने कोरोना समेत 22 बीमारियों के लिए मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट विकसित किया है

कंपनी का दावा है कि टूनैट 22 संक्रामक बीमारियों की जांच कर सकता है, जिसमें टीबी, एच1एन1, डेंगू, एचआईवी, हेपेटाइटिस आदि शामिल है। साथ ही कंपनी अतिरिक्त 43 बीमारियों की जांच पर काम कर रही है, जिसमें कोरोनावायरस शामिल है। टूनैट 60 मिनट में नतीजे देता है और यह जेब पर भारी नहीं है। यह उपकरण बैटरी से परिचालित होता है और बुनियादी ढांचे में विस्तार किए बिना कई केंद्रों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देसी तकनीक को भारतीय चिकित्सा शोध परिषद ने साल 2018 में मंजूरी दी थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूएचओ ने कई देशों में अध्ययन के बाद जनवरी 2020 में टूनैट को टीबी की जांच में कारगर बताया।

निचले स्तर पर रेटिंग डाउनग्रेड

जश कृपलानी
मुंबई, 4 मार्च

हाल के महीनों में नजर आए रेटिंग डाउनग्रेड के मामले जनवरी में रुक गए और डाउनग्रेड की गई बॉन्ड प्रतिभूतियों की कीमत 15 महीने के निचले स्तर पर आ गई। हालांकि डेट फंड मैनेजरों और रेटिंग विश्लेषकों ने कहा कि उधारी का बाजार अभी मुश्किलों से बाहर नहीं निकला है और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और अन्य क्षेत्र अभी भी दबाव का संकेत दे रहे हैं।

आईडीएफसी म्युचुअल फंड के फंड मैनेजर अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा, निचली रेटिंग वाली कुछ एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों पर दबाव बना हुआ है, जिसमें आगे और डाउनग्रेडिंग हो सकती है।

एक फंड मैनेजर ने कहा, डाउनग्रेडिंग के लिहाज से पिछले डेढ़ साल काफी खराब रहे हैं। लेकिन अभी भी यह कहना मुश्किल है कि व्यवस्था में दबाव का मामला पीछे छूट गया है। अभी भी कुछ एनबीएफसी की गैर-निष्पादित आस्तियों में बढ़ोतरी हो रही है।

जनवरी में रेटिंग एजेंसियों ने 35 बॉन्डों को डाउनग्रेड किया, जिसकी कीमत 17,129 करोड़ रुपये थी। यह जानकारी बाजार नियामक सेबी के आंकड़ों से मिली। पिछले महीने जितनी कीमत की डाउनग्रेडिंग हुई थी, यह उसके मुकाबले 80 फीसदी कम है। रेटिंग अधिकारियों ने कहा कि डाउनग्रेडिंग में कमी की वजह व्यवस्था में घट रहा दबाव हो सकती है। रेटिंग एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ज्यादा उधारी वाली वित्तीय इकाइयां पहले ही रेटिंग की ज्यादा कवायद का सामना कर चुकी है। ऐसे में व्यवस्था में डाउनग्रेडिंग का जोखिम कम हुआ है। हालांकि पूरे सुधार में कुछ समय लग सकता है। इसके अलावा बाहरी कारणों मसलन कोरोनावायरस से आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध भी कंपनियों की क्रेडिट की गुणवत्ता पर असर डाल सकता है।

डाउनग्रेड की संख्या अब तक हालिया वित्त वर्षों के सबसे खराब आंकड़ों से एक रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में डाउनग्रेडिंग की मात्रा 14 लाख करोड़ रुपये रही है, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 60 फीसदी ज्यादा है।

फरवरी में रेटिंग एजेंसियों ने वोडाफोन आइडिया के कॉरपोरेट बॉन्ड को डाउनग्रेड किया था, जो समायोजित सकल राजस्व के बकाए को लेकर दबाव में है। 31 मार्च 2019 को दूरसंचार कंपनी पर एनसीडी के जरिये कुल बकाया उधारी 10,352 करोड़ रुपये थी और यह जानकारी कंपनी की सालाना रिपोर्ट से मिली।

रेटिंग एजेंसियों ने येस बैंक को भी डाउनग्रेड कर बीबीबी से बीबीबी (नकारात्मक) कर दिया है। हालांकि फंड मैनेजरों का मानना है कि ज्यादातर दबाव बॉन्ड की कीमत में समाहित कर लिए गए हैं।

बाजार के भागीदारों ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता वाली एनबीएफसी और बॉन्ड जारी करने वाली अन्य कंपनियों के लिए फंडिंग उपलब्ध है क्योंकि आरबीआई के एलटीआरओ व व्यवस्था में नकदी में सुधार के बाद फंड की लागत घटी है।

जनवरी में निवेशकों ने क्रेडिट रिस्क फंडों से 1,214 करोड़ रुपये की निकासी की, जो इस वित्त वर्ष के दौरान इस श्रेणी से हुई सर्वोच्च निकासी के मुकाबले कम है। मई में इस श्रेणी से करीब 4,000 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी।

रकम जुटाने के लिए म्युचुअल फंडों से बात कर रहा येस बैंक

निवेशक पाने की राह में लॉक इन की शर्त बनेगा अवरोध

हंसिनी कार्तिक
मुंबई, 4 मार्च

येस बैंक ने 30 से 50 करोड़ डॉलर इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए देसी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (म्युचुअल फंडों) से संपर्क साधा है। रेटिंग में हुई डाउनग्रेडिंग और लोनबुक पर दबाव के बीच यह देखने को मिला है।

अगर निजी बैंक इस दौर में रकम जुटाने में सक्षम होता है तो उसे कुछ राहत मिलेगी। लेनदार को हालांकि कुछ और रकम जुटाने पर काम करना होगा ताकि चिंता दूर की जा सके। बैंक का लक्ष्य कुल मिलाकर 2 अरब डॉलर जुटाने का है।

येस बैंक पूंजी जुटाने के लिए महीनों से संघर्ष कर रहा है। बैंक को दिसंबर 2019 की तिमाही का नतीजा टालना पड़ा था क्योंकि रकम जुटाने की प्रक्रिया ने ज्यादातर आला प्रबंधन का समय ले लिया।

रकम जुटाने की कवायद से जुड़े निवेश बैंकरों ने कहा कि बैंक ने इक्विटी शेयर के लिए देसी म्युचुअल फंडों से संपर्क किया है। एक बैंकर ने कहा, इस पेशकश में दिलचस्पी तो है, लेकिन अभी तक मजबूत प्रतिबद्धता नहीं जताई गई है। बैंक उन म्युचुअल फंडों से बातचीत कर रहा है, जो साल 2019 में रकम जुटाने के दौर में शामिल हुए थे। अगस्त 2019 में येस बैंक ने क्यूआईपी के जरिये 1,930 करोड़ रुपये जुटाए थे।

फंड मैनेजरों ने लॉक इन अवधि वाली प्रतिभूतियों में रकम लगाने के मामले में अपने ऐतराज के बारे में बता दिया है। हालांकि समाधान निकालने के लिए बातचीत हो रही है। रकम जुटाने की योजना पर ताजा स्थिति जानने के लिए बैंक को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला।

बैंकर ने कहा, राइट्स आधार पर इक्विटी शेयर जारी करने की भी योजना है। राइट्स इश्यू में भागीदारी के लिए निवेशक को शेयरधारक होना जरूरी है और इसी वजह से कुछ मौजूदा शेयरधारकों (म्युचुअल फंडों) से संपर्क किया गया है। निवेशकों की अंतिम मंजूरी अगले तीन दिन में मिलने की संभावना है। जब बैंक की नियंत्रक हिस्सेदारी बिक्री पर सौदा हो जाएगा तो ये निवेशक अपने निवेश की निकासी कर सकते हैं।

12 फरवरी को येस बैंक ने दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा में देर कर दी क्योंकि वह जे सी फ्लावर्स समेत संभावित निवेशकों से इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए बातचीत कर रहा था। बैंक को जे सी फ्लावर्स और टाइडन पार्क कैपिटल मैनेजमेंट समेत कई निवेशकों से गैर-बाध्यकारी अभिरुचि मिली थी।

लेनदार की तरफ से पूंजी जुटाने में लगातार हो रही देर के कारण पिछले महीने इक्रा ने बैंक के टियर-1 व टियर-2 बॉन्डों की रेटिंग ए से बीबीबी प्लस कर दी थी।

सेवा क्षेत्र का फरवरी में शानदार प्रदर्शन

पीएमआई फरवरी में बढ़कर 57.5 पर पहुंचा, जो जनवरी में 55.5 था। लेकिन रोजगार वृद्धि तीन महीनों में सबसे कम

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 4 मार्च

निर्यात और नए ऑर्डर बढ़ने से सेवा क्षेत्र की वृद्धि फरवरी में 7 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गईं। निक्केई इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) फरवरी में 57.5 पर रहा, जो जनवरी में 55.5 की तुलना में अधिक है। पीएमआई का 50 अंक से अधिक होना विस्तार और इससे कम होना गिरावट को दर्शाता है।

प्रत्येक संकेतक में वृद्धि के बावजूद क्षेत्र में सृजित रोजगार अवसरों की संख्या गिरकर तीन महीने के निचले स्तर पर आ गई। सेवा क्षेत्र की वृद्धि नवंबर से मजबूत हो रही है। उससे पहले के दो महीनों में सेवा क्षेत्र की वृद्धि में गिरावट आई थी। सेवा क्षेत्र में वृद्धि का रुझान विनिर्माण गतिविधियों के समान है। विनिर्माण गतिविधियों में जनवरी में भारी तेजी आई है। जनवरी में विनिर्माण पीएमआई 55.3 रहा, जो करीब 8 वर्षों में सबसे अधिक है।

उद्योग से जुड़े लोगों ने कहा कि सेवाओं में फरवरी में वृद्धि मुख्य रूप से नया वैश्विक कारोबार आने की वजह से हुई है। इससे कंपनियों को 2019 के भारी उतार-चढ़ाव से उबरने में मदद मिली है। चुनौतियों के बावजूद निर्यात में 2019 में लगभग पूरे वर्ष में वृद्धि रही। हालांकि लगातार 11 महीनों तक बढ़ोतरी के बाद जनवरी में गिरावट दर्ज की गई। ज्यादातर पैनलिस्ट इसकी वजह चीन, यूरोप और अमेरिका से कमजोर मांग बताई थी।

फरवरी में नए काम के ऑर्डरों में भी सात साल में दूसरी सबसे अधिक वृद्धि रही। नीति निर्माताओं को इस बात से खुशी होगी कि काम के ज्यादातर नए ऑर्डर घरेलू बाजार से आए हैं। ये 2018 में आर्थिक गिरावट के लंबे दौर के बाद घरेलू मांग में बढ़ोतरी का संकेत देते हैं। इसके नतीजतन फरवरी में लगातार पांचवें महीने बिक्री में बढ़ोतरी हुई। सर्वेक्षण में शामिल कंपनियों ने मददगार आर्थिक स्थितियों और सरल सरकारी नीतियों का संकेत दिया। उपभोक्ता सेवाओं में वृद्धि सबसे उल्लेखनीय रही। पिछले महीनों में परिवहन और भंडारण कंपनियों ने तगड़ी वृद्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही में बकाया काम में बढ़ोतरी के बावजूद सेवा प्रदाताओं ने फरवरी में नियुक्तियों पर अंकुश लगाए रखा। कुछ कंपनियों ने मौजूदा काम के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने के मद्देनजर कर्मचारियों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं की। हालांकि इसके बावजूद पांच उप-क्षेत्रों में से चार में रोजगार के आंकड़े बढ़े हैं। केवल वित्त एवं बीमा में रोजगार के मौके नहीं बढ़े।

आईएचएस मार्किट के मुख्य अर्थशास्त्री और रिपोर्ट की लेखक पोल्लयन्ना डी लीमा ने कहा, 'विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में नए काम में सकारात्मक बढ़ोतरी से पता चलता है कि मार्च में फ्रि निजी क्षेत्र के उत्पादन में अहम इजाफा होगा, जो अंतिम तिमाही के जीडीपी के लिए अच्छा होगा।'

हालांकि कंपनियां अपने लाभ को बढ़ाने में कामयाब रही हैं क्योंकि नए कारोबारों में ऊंची वृद्धि से कच्चे माल की कीमतों में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई। कच्चे माल की औसत लागत में वृद्धि धीमी रही। सर्वेक्षण में शामिल ज्यादातर लोगों ने कहा कि लागत के बोझ में सबसे अधिक योगदान खाद्य, श्रम, सामग्री और तेल की कीमतों का है। लेकिन सेवाओं के लिए वसूली जाने वाली औसत कीमतों में कम बढ़ोतरी हुई है। शुल्क में बढ़ोतरी जनवरी की तुलना में कम थी। केवल छह फीसदी कंपनियों ने अपनी फीस बढ़ाई।

सेवा क्षेत्र की वृद्धि सात साल में सबसे अधिक

- सेवा क्षेत्र की वृद्धि नवंबर से हो रही है मजबूत
- सेवाओं में फरवरी में वृद्धि मुख्य रूप से नया वैश्विक कारोबार आने की बदौलत हुई
- चुनौतियों के बावजूद निर्यात में 2019 में पूरे वर्ष में वृद्धि रही
- फरवरी में नए काम के ऑर्डरों में भी सात साल में दूसरी सबसे अधिक वृद्धि रही

टाटा मुंद्रा बंद करेगी पांच राज्यों की बिजली

श्रेया जय
नई दिल्ली, 4 मार्च

मुंद्रा स्थित टाटा पावर के अत्यधिक बड़े बिजली संयंत्र से 11 मार्च से पांच राज्यों को बिजली की आपूर्ति रोक दी जाएगी। कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी और प्रबंध निदेशक प्रवीर सिन्हा ने कहा, 'यदि राज्यों के साथ समाधान नहीं होता है तो हम धीरे धीरे इकाइयों को बंद करना शुरू कर देंगे।'

यह कड़ा कदम यूएमपीपी से आने वाली बिजली के लिए खरीदार राज्यों द्वारा शुल्क में वृद्धि करने पर सहमत नहीं होने से उठाया जा रहा है। मुंद्रा से गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र को बिजली की आपूर्ति होती है।

गुजरात स्थित यूएमपीपी सात वर्षों से नियामकीय गतिरोध में उलझा हुआ है जो आयातित कोयले की बढ़ी हुई लागत के कारण चरम पर पहुंच गया है। अप्रैल 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कोयले की बढ़ी हुई लागत के एवज में टाटा पावर को किसी तरह की क्षतिपूर्ति करने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) को टाटा पावर और बिजली खरीद करने वाले राज्यों के बीच बिजली खरीद समझौते के तहत मुंद्रा के लिए कोई संभावित राहत का उपाय निकालने का भी निर्देश दिया था।

गुजरात सरकार ने एक समिति बनाई थी जिसने परियोजना को चालू रखने में मदद करने के लिए कंपनी और ऋणदाताओं के लिए एक संशोधित टैरिफ और बट्टे खाते का खाका पेश किया था। समिति ने मुंद्रा से आपूर्ति की जाने वाली बिजली की दर बढ़ाने का निर्णय लिया था। हालांकि, कोई भी राज्य इसके लिए तैयार नहीं हुआ था।

सिन्हा ने इस समाचार पत्र को बताया था कि समिति की सिफारिशों को मानने के लिए वे राज्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं।

एयर इंडिया में एनआरआई खरीद सकेंगे 100 फीसदी हिस्सेदारी

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 4 मार्च

सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के निजीकरण में रुचि को बढ़ाने के लिए सरकार ने भारत की नागरिकता रखने वाले अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को विमानन कंपनी में 100 फीसदी की हिस्सेदारी सौंपने की अनुमति दे दी है।

एक छोटे से बदलाव से एयर इंडिया में विदेशी निवेश के नियमों को अन्य निजी विमानन कंपनियों के बराबर कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे विमानन कंपनी में निवेश आकर्षित करने के मौके में इजाफा होगा।

जावड़ेकर ने कहा, 'भारतीय नागरिकता वाले अनिवासी भारतीयों को एयर इंडिया में निवेश करने की अनुमति होगी। इससे नए निवेशों को आकर्षित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। यात्रियों को अधिक से अधिक बेहतर सेवाएं मिलना जारी रहेगा और इससे कारोबारी परिदृश्य में भी सुधार आएगा।'

सरकार ने जनवरी में एयर इंडिया सहित उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस में अपनी समूची हिस्सेदारी बेचने के लिए अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए थे। इसमें एयर इंडिया और सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज की संयुक्त उद्यम एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 50 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए भी अभिरुचि पत्र मंगाने का फैसला शामिल था।

हालांकि, विमानन कंपनी में एनआरआई को 100 फीसदी निवेश करने की अनुमति का फैसला बहुलांश हिस्सेदारी रखने और पूर्ण निर्णय लेने की शक्ति का उल्लंघन भी नहीं होगा। एनआरआई निवेशों को घरेलू निवेशों के तौर पर देखा जाएगा।

बहुलांश हिस्सेदारी और पूर्ण निर्णय स्वामित्व (एसओईसी) ढांचे के तहत नियम है कि किसी खास देश से विदेशों के लिए उड़ान भरने वाले विमानन कंपनियों की बहुलांश हिस्सेदारी उस देश की सरकार या उसके नागरिकों के पास होनी चाहिए।

विमानन उद्योग में इस नियम को पूरी दुनिया में अपनाया जाता है।

फिलहाल, एनआरआई एयर इंडिया में केवल 49 फीसदी हिस्सेदारी ही रख सकते हैं। सरकार के स्वीकृत माध्यम से विमानन कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए सीमा भी 49 फीसदी ही है।

मौजूदा नियमों के मुताबिक अधिसूचित घरेलू विमानन कंपनियों में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति है जो कुछ निश्चित शर्तों के अधीन है जिसमें यह भी शामिल है कि यह नियम विदेशी विमानन कंपनियों के लिए प्रभावी नहीं होगा।

अधिसूचित विमानन कंपनियों के मामले में 49 फीसदी एफडीआई की अनुमति स्वत: मंजूरी मार्ग से है और उससे ऊपर के निवेश के मामले में सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत है। विमानन कंपनी को बेचने के अपने प्रयास के हिस्से के तौर पर सरकार ने पेशकश को आकर्षक बनाने के लिए बहुत सारे शर्तों को बदल दिया है। इसमें पिछली बार की 76 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की जगह 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला भी शामिल है। शर्तों में किए गए अन्य बदलावों में कर्ज में कमी का फैसला भी है जिसके तहत सफल बोलीदाता के ऊपर केवल 23,286.5 करोड़ रुपये की ऋण देनदारी होगी जबकि देयताओं का निर्धारण लेनदेन पूरा होने के समय पर मौजूदा परिसंपत्तियों के आधार पर होगा।

कंपनी संशोधन विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 4 मार्च

मंत्रिमंडल ने आज कंपनी अधिनियम 2013 में 72 बदलावों को मंजूरी दे दी। इनमें छोटी-मोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी से हटाने और 'ब्रांड भारत' को मजबूत करने के लिए घरेलू कंपनियों को सीधे विदेश में सूचीबद्ध होने की मंजूरी देने पर जोर दिया गया है।

मंत्रिमंडल ने कंपनी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसे संसद के चालू सत्र में पेश किए जाने के आसार हैं। इस संशोधन के जरिये कंपनियों पर कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की अनुपालना का बोझ हल्का किया जाएगा। पचास लाख या उससे कम खर्च करने की जिम्मेदारी वाली कंपनियों को छूट दी जाएगी। ऐसी कंपनियों को सीएसआर समिति बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अगर कोई कंपनी किसी वर्ष में अपने औसत लाभ की दो फीसदी से अधिक राशि सीएसआर पर खर्च करती है तो वह अगले वित्तीय वर्षों में अतिरिक्त राशि को आगे ले जा सकती है। वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं को बताया, 'हम कारोबारियों के लिए कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम कुछ खंडों को हटाकर कुछ कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना चाहते हैं।'

गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की उल्लिखत श्रेणियों के लिए एक नई धारा 129 जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। ये कंपनियां सालाना नतीजे पेश करने के साथ आवधिक आधार पर भी अपने नतीजे देंगी ताकि आवधिक आर्थिक आंकड़ों को ज्यादा वैज्ञानिक बनाया जा सके।

सरकार ने 66 समझौते लायक गड़बड़ियों (कंपाउडेबल ऑफेंस) में से 23 की श्रेणी बदलने की योजना बनाई है। इनके लिए आंतरिक विवाद निपटाना ढांचा होगा। कंपनी संशोधन विधेयक में 11 गलतियों के लिए दंड जुर्माने तक सीमित रहेगा और इनमें कारावास का खंड हटाया जाएगा।

छह गलतियों के लिए जुर्माना घटाया जाएगा, जिन्हें पहले ही अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। घरेलू कंपनियों की विदेशी एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता के बारे में कंपनी मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि इसके लिए अधिनियम में प्रावधान शामिल किया जाएगा और अगले कुछ महीनों में नियमों का व्यापक खाका तैयार किया जाएगा। इस समय भारतीय कंपनियों के पास विदेशी निवेशकों का निवेश हासिल करने के लिए केवल अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स (एडीआर) या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स (जीडीआर) के दो विकल्प हैं।

प्रावधानों में नरमी

- 23 प्रावधानों को आंतरिक स्तर पर सुलझाया जाएगा
- 7 को कंपनी अधिनियम से बाहर किया जाएगा
- 11 में दंडस्वरूप केवल जुर्माना भरना होगा
- 5 में वैकल्पिक ढांचा होगा
- 6 में दंड को तर्कसंगत बनाया जाएगा

2021 के पूर्वार्द्ध में चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 4 मार्च

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) वर्ष 2021 की पहली छमाही में चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण की योजना बना रहा है। भारत ने ऐस समय तीसरे चंद्रयान मिशन की घोषणा की है, जब पिछला मिशन सितंबर 2019 में क्रैश लैंडिंग के कारण सफल नहीं हो पाया था।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन और प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक सभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण 2021 की पहली छमाही में होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 मिशन का ढांचा चंद्रयान-2 से सीखे गए सबकों के आधार पर तय किया गया है।

जीसैट-1 प्रक्षेपण टला

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने तकनीकी वजहों से जीसैट-1 उपग्रह को ले जाने के लिए तैयार जीएसएलवी-एफ10 का प्रक्षेपण स्थगित करने का फैसला किया है। देश के पहले भू-पर्यवेक्षण उपग्रह को ले जा रहे रॉकेट जीएसएलवी-एफ10 का प्रक्षेपण 5 मार्च, 2020 को होना था। इसरो ने कहा कि नई तारीख की सूचना उचित समय पर दी जाएगी।

10 बैंकों के विलय को मंजूरी

पृष्ठ 1 का शेष

वित्त मंत्री ने कहा, 'इन तीन बैंकों की शाखा का नेटवर्क पहले की तरह 9,400 बना हुआ है और एटीएम मशीनों की संख्या भी 13,000 है और कुल कर्मचारी 85,000 हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का परिचालन मुनाफा 2019-20 की तीसरी तिमाही में 11.4 फीसदी बढ़ा है, वहीं जमा में भी 8.8 फीसदी और पूंजी अनुपात में 1.71 फीसदी का इजाफा हुआ है।'

उन्होंने कहा कि विलय के बाद खुदरा ऋण मंजूरी में लगने वाला समय 23 दिन से घटकर 11 दिन रह गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि एकीकरण से बैंकों के कामकाज पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, 'कोर बैंकिंग संचालन को प्रभावित किए बिना बैंकों की सभी सेवाएं पहले की तरह सुचारू रूप से चलेंगी और एकीकरण ग्राहकों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।' बैंकों की बैलेंस शीट और शेयरों का भी विलय होगा और एकीकरण पूरा होने में कम से कम एक साल का वक्त लगेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के मामले में तकनीकी एकीकरण अब तक पूरा नहीं हो पाया है और वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इसके अगली तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 16

अनिश्चितता का अंत

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 10 सरकारी बैंकों का चार बैंकों में विलय करने की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इस कवायद से जुड़ी लंबी अनिश्चितता का अंत हो गया है।

गत माह मंत्रिमंडल की तीन बैठकों में इसे मंजूरी नहीं मिलने से विलय की तारीख में देरी होने की अटकल लगने लगी थीं। हालांकि वित्त मंत्री ने इस विलय की घोषणा गत वर्ष 30 अगस्त को की थी। इस प्रक्रिया में शामिल बैंकर चिंतित थे क्योंकि अधिसूचना के बाद आमतौर पर प्रक्रिया पूरी करने में 40-45 दिन का समय लगता है। अब इस काम को तेजी से अंजाम देना होगा क्योंकि बैलेंस शीट और शेयरों के एकीकरण के लिए 1 अप्रैल से पहले 30 दिन से भी कम समय बचा है। मंत्रिमंडल की मंजूरी में देरी संभवत: इसलिए हुई क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय होने के बाद उसके वित्तीय नतीजे अच्छे नहीं रहे। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में इस संयुक्त उपक्रम को 1,407 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा मुख्यतौर पर अधिक प्रोविजनिंग की वजह से हुआ। अब बैंक की दिक्कतें और बढ़ गई हैं क्योंकि 10,387 करोड़ रुपये की राशि फंसे कर्ज में तब्दील हो गई है।

वित्त मंत्रालय ने विलय के लिए बैंकों का चयन किस आधार पर किया इसके पीछे कोई दलील मौजूद नहीं है। जाहिर है तीन कमजोर बैंक मिलकर एक मजबूत बैंक नहीं बन सकते। दरअसल सरकार ने घोषणा कर दी थी और अब उसके पास वापसी का रास्ता नहीं था। इन बैंकों के अंशधारकों को भी आगे की राह के लिए कुछ निश्चितता की आवश्यकता थी।

अब जबकि निर्णय लिया जा चुका है तो सरकार के लिए अच्छा यही होगा कि वह सरकारी बैंकों के लिए आवश्यक वास्तविक सुधारों पर काम करे। ऐसे समय पर इसकी खास आवश्यकता है जबकि चरणबद्ध जमा में उनकी हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। हाल के वर्षों में सरकारी बैंकों में अंशधारक की संपत्ति का नुकसान दर्शाता है कि ये बैंक राह भटक गए हैं। उदाहरण के लिए एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक जिसे सूचीबद्ध हुए तीन साल से भी कम वक्त हुआ है, वह बाजार पूंजीकरण में पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) को पीछे छोड़ चुका है। जबकि परिसंपत्ति खाते और कुल जमा के मामले में पीएनबी उससे बहुत आगे है। बैंक ऑफ बड़ौदा का बाजार पूंजीकरण भी कमोबेश उतना ही है जितना कि एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक का।

सरकारी बैंकों के सुधार के लिए अभी नहीं या कभी नहीं जैसे हालात बन गए हैं। जिन सुधारों को अंजाम देना जरूरी है उनमें स्वामित्व ढांचा और वरिष्ठ प्रबंधन के वेतन भत्ते शामिल हैं। लक्ष्य यह होना चाहिए कि बैंको को सरकारी स्वामित्व से मुक्त किया जाए। इसमें कम वेतन, राजनीतिक हस्तक्षेप और जांच एजेंसियों के शिकंजे की आशंका शामिल है। सरकार को इन बैंकों के स्वामित्व को एक होल्डिंग कंपनी में विभाजित करना चाहिए जिसके बोर्ड द्वारा अलग-अलग बैंकों के बोर्ड की नियुक्ति करनी चाहिए।

होल्डिंग कंपनी अपनी पूंजी का इस्तेमाल इन बैंकों के पूंजीकरण के लिए कर सकती है। उसे इन बैंकों की निर्णय प्रक्रिया राजनेताओं और नौकरशाहों से बचाना चाहिए। उसे एक ऐसा वेतन ढांचा तैयार करना चाहिए जो बैंकरों को प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत करे। इसे परिसंपत्ति के प्रदर्शन से जोड़ा जाना चाहिए। पीजे नायक समिति ने आवश्यक सुधारों का क्रम और तरीका सुझाया है। बहरहाल, सरकार ने उक्त अनुशंसाओं की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास किए बिना ही प्रावधानों का इस्तेमाल करना तय किया है।

अजय मोहंती

बड़े पैमाने पर परोपकार हो नियमन से मुक्त

भारत को बहुत बड़े पैमाने पर परोपकार की आवश्यकता है। आज देश के अमीर तबके के लोगों के पास ऐसा करने की पूरी गुंजाइश है। इस संबंध में जानकारी प्रदान कर रहे हैं श्यामल मजूमदार

बताया जाता है कि आय कर विभाग ऐसे प्रावधानों पर जोर दे रहा है जिनके तहत सन 1973 के पहले कंपनियों में हिस्सेदारी रखने वाले परोपकारी संस्थानों को अपना ऐसा निवेश समेटना होगा। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कई हलकों में मान्यता है कि परोपकारी न्यास को अपने कर छूट के दर्जे का दुरुपयोग कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए नहीं करना चाहिए।

परंतु यह गलत संदर्भ है। सवाल दरअसल यह होना चाहिए कि क्या अंशधारिता का मसला, इसका दायरा और फर्म के ऊपर नियंत्रण अथवा इन संस्थानों का उद्देश्य और इनका प्रदर्शन ऐसे नियंत्रण को प्रदर्शित करता है?

पूरा ध्यान और विधि निर्माण में इस बात पर दिया जाना चाहिए कि नियंत्रण का किस हद तक इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या यह पूरी तरह स्वामित्व संस्था के लाभ के लिए है या फिर संगठन के समग्र कारोबारी लक्ष्य के लिए तथा समस्त संबद्ध अंशधारकों की समृद्धि के लिए?

जरा अंशधारिता के रुझान पर विचार कीजिए। भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनकी अंशधारिता का आधार विविधतापूर्ण है। उदाहरण के लिए एलऐंडटी। दूसरी ओर परिवार द्वारा चलाई जाने वाली कंपनियां भी हैं, मसलन टाटा संस। इन कंपनियों में बहुलांश स्वामित्व टाटा न्यास समूह का है और इसकी प्रमुख अंशधारिता वाली कंपनी है टाटा समूह। तीसरा प्रकार विदेशी कंपनी के नियंत्रण वाली अनुषंगी कंपनी का है, मसलन हिंदुस्तान यूनिलीवर। इन कंपनियों का प्रदर्शन और उद्देश्य यह नहीं दर्शाता कि कोई भी एक वर्ग इन संदर्भों में श्रेष्ठ या कमतर है।

इसी तरह कई कंपनियां जिनमें तमाम तरह की अंशधारिता के रुझान रहते हैं, वे अच्छी तरह चल रही हैं। इनमें वे कंपनियां भी शामिल हैं जहां परोपकारी संस्थान अपनी अंशधारिता के प्रभाव से अहम भूमिका रखते हैं।

वास्तव में सरकार को समान कार्य परिस्थितियां प्रदान करने के बारे में विचार करना चाहिए। इसके लिए वह सन 1973 से पहले का दर्जा बहाल कर सकती है। उसके अधीन फाउंडेशन आय कर रियायत के साथ हिस्सेदारी रख सकते और अन्य फाउंडेशन भी टाटा और बिड़ला न्यास के समकक्ष हो पाते।

एक के बाद एक सरकारों ने यह इच्छा प्रकट की है कि कंपनियों को सामाजिक विकास योगदान की लागत को आक्रामक तरीके से साझा करना चाहिए। दरअसल कंपनियों द्वारा अपने मुनाफे का दो फीसदी हिस्सा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय करना वांछित है।

भारत को बहुत बड़े पैमाने पर परोपकार की आवश्यकता है। आज देश के अमीर तबके के लोगों के पास ऐसा करने की पूरी गुंजाइश है। उदाहरण के लिए अमेरिका में परोपकारी दान उसके जीडीपी का करीब दो फीसदी है। यदि भारत का कारोबारी जगत इसे अपनाता है तो यह राशि करीब 60 अरब डॉलर तक होगी।

अन्य स्थानों की तरह भारतीय उद्यमी जगत भी अपनी संपत्ति की बहुत बड़ी हिस्सेदारी अन्य कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है। प्रवर्तकों को अपनी हिस्सेदारी का बड़ा हिस्सा परोपकार में दान करने की इजाजत देकर और ऐसे परोपकारी संस्थानों को आय कर में रियायत प्रदान करने से सरकार को संपत्ति को सामाजिक कार्यों में स्थानांतरित करने के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता मिलेगी।

टाटा और बिड़ला की तरह दुनिया के कुछ जानेमाने संगठन मसलन हाइनकेन, आइकिया, रॉबर्ट बॉस्क, कार्ल्सबर्ग आदि का स्वामित्व भी फाउंडेशनों के पास है। वालेनबर्ग फाउंडेशन प्रत्यक्ष रूप से या निवेश फर्म के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से एबीबी, ऐस्ट्राजेनेका और एटलस कोपको आदि का स्वामित्व रखता है।

यह विचार कि परोपकारी संस्थान कारोबार नहीं चला सकते, उस आकांक्षा के विपरीत है जिसके तहत कारोबारों को अधिकाधिक परोपकारी बनाने की बात कही जाती है। यह बात हमें भारत में सन 1970 के दशक के विचारों की ओर ले जाती है। आज यह बात पूरी तरह साबित हो चुकी है कि यह एक अतीतगामी कदम था। फाउंडेशनों को बिना आय कर रियायत गंवाए हिस्सेदारी रखने का निर्णय भी ऐसा ही एक निर्णय था। कारोबार में अविश्वास के चलते सरकार ने सन 1969 में एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम लागू किया और उसके बाद सन 1973 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम भी। आखिरकार इनके चलते सन 1991 का संकट सामने आया और विनियमन हुआ।

परंतु उस सकल अविश्वास ने कुछ हद तक विश्वास के लिए भी राह तैयार की। यानी अब वक्त आ गया है कि बड़े पैमाने पर होने वाली परोपकारिता को भी तिलांजलि दे दी जाए। सरकार सन 1973 के बाद के समय से भी सबक सीख सकती है। जब आईबीएम और कोक बाहर निकले, यूनीलीवर ने सरकार से इस विषय पर वार्ता शुरू की कि वह 51 फीसदी अंशधारिता को विराम बिंदु बना दे। उसने कहा कि ऐसा इस शर्त पर किया जाएग कि ऐसे बहुराष्ट्रीय निगम पिछड़े इलाकों के विकास के लिए तथा उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में काम करेंगे।

जनता पार्टी सरकार ने शायद इसकी इजाजत भी दे दी होती (स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस उस सरकार में उद्योग मंत्री थे) लेकिन वह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। आखिरकार उसके बाद सत्ता में आई इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। 'उदारीकरण' शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल उनकी सरकार के उद्योग मंत्री नारायण दत्त तिवारी ने किया था। कहने का तात्पर्य यह कि शायद मसला नियंत्रण के स्वरूप का नहीं बल्कि परिणामों की वास्तविकता का है।

अगर हम टाटा ट्रस्ट का उदाहरण लें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि टाटा संस में अपनी भागीदारी की मदद से उन्होंने कई नए कारोबार स्थापित करने में सहायता की। टाटा संस की अंशधारिता में ट्रस्ट की हिस्सेदारी दो तिहाई है। यानी यह संपत्ति सामाजिक उद्देश्यों के लिए वर्गीकृत परिसंपत्ति समर्थन से एकत्रित हुई।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो चीज टूटी ही नहीं है, उसे ठीक करने की कोशिश ही क्यों करनी?

वैश्विक व्यापार जगत को कितना प्रभावित करेगा कोरोनावायरस

नीति नियम
मिहिर शर्मा

क्या भविष्य के आर्थिक इतिहासकार वर्ष 2020 के शुरुआती महीनों पर इस तरह नजर डालेंगे कि यही वह अवधि थी जब वैश्वीकरण की लहर के पिछड़ने की शुरुआत हुई? पिछले एक दशक के दौरान दुनिया भर के लोकप्रिय नेताओं की बातों और इस दौरान आए तकनीकी बदलाव ने निश्चित तौर पर यह बताया कि वैश्वीकरण पहले की तरह कारगर नहीं रहा। हाल के वर्षों में विश्व व्यापार घटा है लेकिन इस संबंध में शोर शराबा हकीकत से ज्यादा हुआ है। कई जगह शुल्क बढ़ाए जाने के बावजूद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्गठन नहीं हुआ है। कुछ कंपनियों ने चीन से दूरी बनाई है लेकिन मोटे तौर पर सब पहले जैसा है।

प्रश्न यह है कि क्या वुहान से फैला कोरोनावायरस सबकुछ बदल देगा। मनुष्यों पर इसका क्या और कितना असर होगा यह बताना मुश्किल है। सन 2009 के स्वाइन फ्लू की तरह यह दुनिया भर में हजारों लोगों की मौत का कारण भी बन सकता है या फिर हालात इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। इससे आधी सदी पहले हॉन्गकॉन्ग फ्लू (हालांकि यह चीन से पनपा था) की तरह बहुत बड़ी तादाद में मौतें भी हो सकती हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक आने वाले समय में यह बीमारी इतनी खतरनाक नहीं रह जाएगी और लोगों में इसके प्रति प्रतिरक्षा तैयार हो जाएगी।

ऐसे में कोरोनावायरस का सबसे बड़ा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हो सकता है क्योंकि वह चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है। चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका स्पष्ट असर है। आधिकारिक आंकड़ों पर तो हमेशा सवाल उठाया जा सकता है लेकिन नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ली गई तस्वीरें भी चीन के औद्योगिक तथा अन्य प्रमुख इलाकों में पिछले आठ सप्ताह के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक तत्त्वों की मात्रा कम होने की गवाही देती हैं। लगभग इसी अवधि में यह वायरस वुहान से पूरे चीन में फैला। इससे करीब 2,500 लोगों की मौत हो गई।

आठ से 10 सप्ताह का समय बहुत मायने रखता है। चीन की अधिकांश कंपनियों और फैक्टरियों ने 25 जनवरी को आरंभ चीनी नव वर्ष के पहले उत्पादन बंद कर दिया था। उस समय निकले शिपमेंट अब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पहुंच रहे होंगे। बंदरगाहों पर आवक पहले ही 20-30 फीसदी कम हो चुकी है। कंपनियों के पास आमतौर पर दो सप्ताह से एक महीने तक की इन्वेंटरी रहती है हालांकि चीन में अवकाश को देखते हुए जनवरी में ही भंडार एकत्रित कर लिया गया होगा। बहरहाल, जब तक मालवहन सहज नहीं होता, दुनिया भर की कंपनियों को कच्चे माल की कमी का सामना करना होगा।

कार कंपनियां तो यह असर महसूस भी करने लगी हैं। याद रहे जो कंपनियां प्रत्यक्ष तौर पर चीन से नहीं जुड़ी हैं वे भी प्रभावित हो रही हैं। इसलिए क्योंकि उनके आपूर्तिकर्ता चीन के कच्चे माल पर निर्भर हो सकते हैं।

ऐसी स्थिति में आपूर्ति श्रृंखलाओं पर क्या असर होगा? कहने का अर्थ यह कि दुनिया के एक विशेष हिस्से में चिकित्सा आपदा के चलते तमाम कंपनियों का काम प्रभावित हो सकता है। सन 2002 में सार्स आपदा के बाद चीन दुनिया की फैक्टरी में तब्दील हो गया। ज्यादातर देशों को अनुमान तक नहीं है कि वे चीन पर किस कदर निर्भर हैं।

यहां तथ्य यह है कि अस्थिरता का ऐसी स्वास्थ्य आपात स्थिति से कोई संबंध नहीं। अधिनायकवादी शासन व्यवस्था हमेशा भंगुर होती है। राजनीतिक अस्थिरता कभी भी सर उठा सकती है। चीन हाल के वर्षों में पुरानी अधिनायकवादी प्रणाली के शासन वाला रहा है। चीन ने मौजूदा नेतृत्व के पहले सामूहिक और कम अधिनायकवादी शासन का मॉडल क्यों अपनाया था, इसे समझने के लिए हमें चीन के अस्थिरतापूर्ण राजनीतिक इतिहास को ध्यान में रखना होगा।

राजनीतिक अस्थिरता के कारण चीन की मुख्यभूमि की आर्थिक गतिविधियों और आपूर्ति में आया धीमापन एक बात है, राजनीतिक कारणों से ऐसा संभव है। उदाहरण के लिए सैन्य तनाव में इजाफा होने की स्थिति में यह कल्पना करना भी असंभव है कि शेष विश्व चीन की फैक्टरियों पर उसी तरह निर्भर रहेगा जैसे अभी है।

सन 2000 से बनी आपूर्ति श्रृंखला लागत कम करने और किफायत बढ़ाने में कामयाब रही है। इस मामले में दुनिया को जल्दी ही पता चल सकता है कि चीन की मुख्यभूमि के उत्पादन पर निर्भरता उसकी निर्भरता कितनी है और यह भी कि संकट के समय उसके पास बहुत सीमित विकल्प हैं।

यही कारण है कि काफी संभव है कि जब तक चीन किसी तरह सुधार नहीं कर लेता है, वैश्वीकरण के इतिहासकार इस मौके को बड़े बदलाव वाले घटनाक्रम के रूप में देखेंगे। हो सकता है मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के नजरिये से और स्थानीय स्थिरता सुनिश्चित करने वाले नीति निर्माताओं की दृष्टि से कोई विकल्प न हो। परंतु क्या यह बात वैश्वीकरण के गणित को बदलने की हैसियत रखती है। जबकि उससे अपेक्षा की जाती है कि वह लागत को न्यूनतम करने और किफायत बढ़ाने का प्रयास करे।

सच तो यही है कि कुछ विनिर्माण इकाइयों का चीन से विस्थापन इसलिए लंबित रहा क्योंकि किफायत का अभाव था और काफी राशि गंवाई जा चुकी थी। पर्ल रिवर डेल्टा और अन्य स्थानों पर बुनियादी ढांचे की कमी और ये दिक्कतें इतनी ज्यादा हैं कि क्लाइंट ने लागत में अहम इजाफे को बरदाश्त करना उचित समझा, बजाय कि अपनी आपूर्ति श्रृंखला को छेड़कर जोखिम पैदा करने के। अब उन्हें यह पता चल चुका है कि ऐसी उथलपुथल जीवन की हकीकत है। बल्कि जब यह उथलपुथल निर्भरता के साथ जुड़ जाए तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। सवाल यह है कि आगे चलकर यह निर्णय प्रक्रिया में किस हद तक बदलाव लाएगा। यदि चीन की फैक्टरियों में जल्दी ही पूरी क्षमता से काम शुरू नहीं हुआ तो काफी संभव है कि हमें अनुमान से बड़ा बदलाव देखने को मिले।

कानाफूसी

अनुपस्थिति की वजह

बिहार के शिक्षा विभाग ने एक शिक्षक को कर्तव्य की उपेक्षा करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। इसमें दिक्कत यह है कि जिस शिक्षक रंजीत कुमार यादव को निलंबित किया गया है उसका दो वर्ष पहले ही निधन हो चुका है। बेगूसराय जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से गत 28 फरवरी को अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया था। यादव को बेगूसराय में एक परीक्षा केंद्र पर उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। इस बीच 17 फरवरी से अनुबंधित शिक्षक स्थायी पदों की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। जब ऐसी रिपोर्ट आईं कि परीक्षा केंद्र पर जाने वाले कई शिक्षकों की पिटाई की जा रही है, तो कई शिक्षकों ने वहां जाने से ही परहेज किया। राज्य शिक्षा बोर्ड ने उन शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश भी दिया जो उत्तर पुस्तिकाएं जांचने नहीं पहुंचे थे।

विकास हो मुद्दा

बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं। इसे देखते हुए राज्य में भाजपा के सहयोगी दलों ने सीट साझेदारी के लिए दांवपेच शुरू कर दिए हैं। राम विलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव से छह महीने पहले ही अपना विजन डॉक्युमेंट जारी करने जा रही है जिसे 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' का नाम दिया गया। इसे 14 अप्रैल को पटना में एक रैली में जारी किया जाएगा। इतना ही नहीं मंगलवार को पार्टी ने अन्य राजनीतिक दलों से भी कहा वे समय रहते अपने चुनाव घोषणापत्र जारी करें ताकि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा सके और वह हिंदू-मुसलमान या जाति का रंग न ले। पार्टी अध्यक्ष पासवान ने कहा कि दिल्ली चुनाव में जो कुछ हुआ वह सबने देखा। उनका इशारा इन चुनावों में हुए ध्रुवीकरण की ओर था।

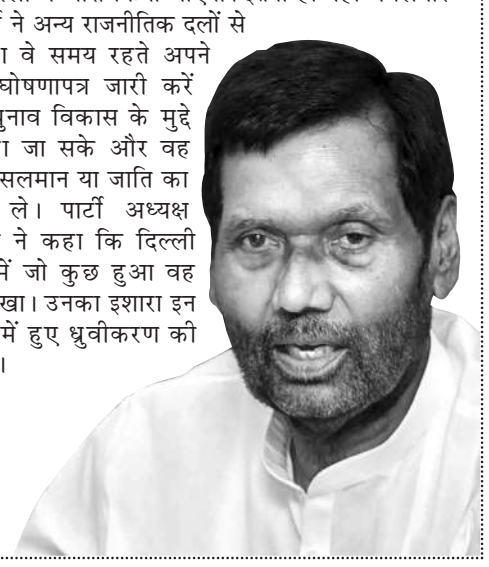

आपका पक्ष

महिलाओं को मिले समान अवसर

डॉ भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि वह किसी समाज के विकास को उसकी महिलाओं के विकास के अनुसार मापते हैं। यानी जहां महिलाएं विकास करती हैं वहां समाज विकास करता है। आगामी 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। उस दिन दुनिया भर की महिलाओं को सम्मान दिया जाता है और नारीवाद का उत्सव मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि महिला दिवस के दिन 8 मार्च को एक दिन के लिए उनका ट्विटर अकाउंट किसी महिला को चलाने का मौका मिलेगा। लेकिन यह केवल सुनने में ही अच्छा लगता है। केवल एक दिन के लिए कोई महिला प्रधानमंत्री या किसी अन्य मंत्री का सोशल मीडिया अकाउंट चला कर क्या बदलाव लाएगी। प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव का मकसद प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियां लोगों से साझा करना और उन्हें प्रेरित करना है। लेकिन यह व्यवहारिकता से कोसों दूर दिखाई पड़ता है। भारत लिंगानुपात रैंकिंग में और गिरता जा रहा है। इसमें वह वर्ष 2018 में 108वें स्थान पर था और यह वर्ष 2019 में गिरकर 112वें स्थान पर आ गया है। किसी भी समाज या देश के लिए महिला नेतृत्व का आगे होना बेहद महत्त्वपूर्ण होता है। लेकिन संसद के दोनों सदनों में महिला सांसदों की संख्या काफी कम है। इसके विपरीत फिनलैंड, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, रवांडा, क्यूबा आदि देशों में महिला नेतृत्व मजबूत है और वे अधिकतर क्षेत्रों में विकास के मामले में भारत से कई गुना आगे है। फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है। यहां कैबिनेट में चार युवा महिलाएं शामिल हैं। भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देशों की सूची में शीर्ष पर है। ऐसे में महिलाओं से संबंधित बाकी विषयों पर बात करना गैर जरूरी लगता है। इन उदाहरणों से भारत को सीख लेनी चाहिए। जहां महिलाओं पर असुरक्षा, भेदभाव, वेतन असमानता आदि समस्याएं हावी हैं। महिलाओं को केवल एक दिन का सपना दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि महिलाओं के विकास के लिए सुरक्षा से लेकर राजनीति, शिक्षा से लेकर उद्यमीकरण हर क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान करने की है।

अनुराधा, नई दिल्ली

सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनी हैं

ट्रंप से सौदा भारत के लिए महंगा

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की यात्रा भारत के लिए फायदेमंद कम, दुखदायी ज्यादा रही। भारत ने जिस उम्मीद से उनका दौरा रखा था उसके आशानुरूप परिणाम नहीं आए क्योंकि ट्रंप ने दो टूक शब्दों में भारत के आयात शुल्क घटाने पर ही किसी तरह के व्यापार करार करने का हवाला दिया। तीन अरब डॉलर के रक्षा सौदों से भारत को कम ट्रंप को अच्छा खासा लाभ हुआ। ट्रंप ने भारत से अनुरोध किया कि वह अपने व्यवसाय के नियमन में थोड़ी ढिलाई बरतें। ट्रंप का भारत के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण देख कर भले लगता है कि वे भारत की वास्तविक मददगार होंगे पर कहीं ना कहीं से इस दौर से चुनावी और राजनीतिक यात्रा दिख रही है।

डॉ रसिकेश नवजात, जौनपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में आधा प्रतिशत तक की कटौती की

धातु, कच्चे तेल की कीमतों में आई उछाल

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 4 मार्च

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में बुधवार को अचानक की गई 0.5 प्रतिशत की कटौती से धातुओं की कीमतों में 1-2 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली है। अमेरिकी फेडरल के कदम से यह संकेत मिलता है कि दुनियाभर में कोरोनावायरस के मामलों में आ रही तेजी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मंदी का जोखिम पैदा हो गया है।

मुंबई के हाजिर बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में 2-3 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) पर तीन महीने के लिए तांबा अनुबंध डिलिवरी में 1 प्रतिशत तक की तेजी के साथ दोपहर में 5,715 डॉलर प्रति टन पर कारोबार हो रहा था। वहीं निकल और जस्ता भी 1.9 प्रतिशत और 0.9 प्रतिशत तक चढ़कर 12,795 डॉलर प्रति टन और 1,993 डॉलर प्रति टन पर थे। एल्युमीनियम की कीमत 0.6 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,733 डॉलर प्रति टन पर थी।

सिर्फ धातुएं ही नहीं, कच्चे तेल, सोने और चांदी की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई। जहां कच्चे तेल की कीमतें इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर 1.4 प्रतिशत चढ़कर 52.59 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं, वहीं भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर इनमें 2.3 प्रतिशत की भारी गिरावट आई। एमसीएक्स पर ये कीमतें 3,537 रुपये प्रति बैरल पर थीं।

कॉमट्रेंड्ज के निदेशक ज्ञानशेखर त्यागराजन ने कहा, 'अमेरिकी फेडरल द्वारा अचानक ब्याज दर कटौती से संकेत मिलता है कि कोरोनावायरस को लेकर स्थिति गंभीर है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य धातुओं और ऊर्जा में और तेजी की उम्मीद के साथ ताजा गिरावट की भरपाई की है। कोरोनावायरस का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट का जोखिम पैदा हो गया है। यही वजह है कि पिछले दो महीनों में सोने की कीमतें में अच्छी तेजी आई है, क्योंकि ऐसी स्थिति में इस धातु में निवेश सुरक्षित समझा जाता है।'

चूंकि अमेरिकी फेडरल की दर कटौती को लेकर संभावना कुछ दिनों से दिख रही थी, इसलिए 0.5 प्रतिशत की कटौती नहीं बल्कि इसका समय आश्चर्यजनक है। सामान्य तौर पर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी निर्धारित बैठक में ब्याज दर में संशोधन की घोषणा करता है। मंगलवार की अचानक दर कटौती वर्ष 2008 में लीमन ब्रदर्स संकट के बाद से उसके द्वारा उठाया गया इस तरह का पहला कदम था। 2008 की मंदी से डॉलर संबंधित सभी जिंसों की कीमतें नीचे आ गई थीं। दरअसल, निवेशकों ने बुधवार को डॉलर की बिक्री पर जोर दिया जिससे प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के मूल्य में गिरावट आई। बुधवार को शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 73.90 पर पहुंच गया था और आखिर में यह 7 पैसे की मामूली तेजी के साथ 73.23 पर बंद हुआ।

आनंद राठी शेयर्स ऐंड स्टॉकब्रोकर्स के निदेशक (जिंस एवं मुद्रा) नवीन माथुर ने कहा, 'फेडरल की ब्याज दर कटौती के बाद एलएमई और एमसीएक्स पर प्रमुख धातुओं में अच्छी तेजी देखी गई है। इसके अलावा डॉलर के कमजोर होने से भी इन धातुओं की चमक बढ़ी है। डॉलर लगातार छह कारोबारी सत्रों से गिरा है। औद्योगिक धातुओं में इस उम्मीद से तेजी आई है कि चीन भी अर्थव्यवस्था को समर्थन मुहैया कराने के लिए ब्याज दरें घटाने के अमेरिकी कदम पर अमल करेगा।'

इस बीच, पिछले कुछ सप्ताहों में सोने और चांदी में तेजी आई है, क्योंकि निवेशकों ने जोखिम वाली परिसंपत्तियों से पैसा निकाल कर इन सुरक्षित दांव समझी जाने वाली धातुओं में लगाने पर जोर दिया है। सोने ने कैलेंडर वर्ष 2019 में लगभग 30 प्रतिशत का प्रतिफल दिया।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) की संयुक्त तकनीकी समिति द्वारा दूसरी तिमाही के दौरान उत्पादन में 600,000 से 10 लाख बैरल प्रति दिन तक की कमी लाने का सुझाव दिए जाने के बाद कच्चे तेल में लगातार तीसरे दिन मजबूती बनी रही।

कोरोनावायरस के प्रसार के बाद चीन और जापान अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मंदी से बचाने के लिए राहत पैकेजों की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। अमेरिकी फेडरल द्वारा ब्याज दरें घटाए जाने के साथ विश्लेषकों को अन्य देशों द्वारा भी इसी तरह के कदम उठाए जाने की संभावना है।

जिंसों के दाम

सराफा	4 मार्च	अंतर
चांदी (रुपये/किलो)	46,205	2.7
सोना (रुपये/10 ग्राम)	43,130	2.0
ऊर्जा		
आईसीई कच्चा तेल (डॉलर/बैरल)	53	1.4
धातु		
निकल (डॉलर/टन)	12,795	1.9
तांबा (डॉलर/टन)	5,725	1.0
जिंक (डॉलर/टन)	1,993	0.9
एल्युमीनियम (डॉलर/टन)	1,733	0.6

अंतर पिछले दिन से प्रतिशत में, स्रोत- आईबीजेए, एलएमई, ब्लूमबर्ग, संकलन- बीएस रिसर्च

सोने के दाम 50 हजार पर पहुंचने के आसार

पृष्ठ 1 का शेष

गौरव रस्तोगी ने सोने में पिछले तीन दशक के उतार-चढ़ाव का विवरण दिया है। सोना जुलाई 1993 से जून 2001 के समेकन के चरण में था। फिर इसमें जून 2001 से नवंबर 2011 तक तेजी रही और सोने की प्रति ग्राम कीमत 400 रुपये से बढ़कर 2,600 रुपये पर पहुंच गई, जो 11 साल में लगभग 6.5 गुना की वृद्धि थी। नवंबर 2011 से मई 2019 तक सोने में समेकन का अन्य चरण देखा गया। तब से यह चढ़कर 4,200 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि यदि पिछली तेजी के चक्र में कीमत 7 गुना बढ़ी, तो अन्य 20 प्रतिशत की वृद्धि काफी हद तक संभव है। इस तेजी के चक्र में अंतरराष्ट्रीय सोने के लिए जेफरीज के क्रिस वुड द्वारा जताई गई प्रति औंस 4,200 डॉलर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सोने में तेजी का शुरुआती चरण निश्चित रूप से आसान नहीं रहेगा और इसमें उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

अरोड़ा ने कहा, 'यदि शेयर बाजार में तेज रफ्तार से गिरावट आती है तो निवेशक मार्जिन कॉल को ध्यान में रखते हुए बिकवाली करेंगे, जिसमें सोना भी शामिल है।' इस तरह की बिकवाली और मुनाफावसूली पिछले शुक्रवार को देखी गई थी और यह फिर से देखी जा सकती है। यदि सोना चढ़ा तो क्या चांदी में भी चमक बढ़ेगी?

सोना-चांदी अनुपात में कीमती धातु के साथ तुलना में चांदी की ज्यादा मजबूती दिख रही है। यह अनुपात मौजूदा समय में 94-95 है। ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि यह निरंतर स्तर नहीं है और इस अनुपात में बदलाव आ सकता है जिसका मतलब है कि चांदी का प्रदर्शन सोने की तुलना में बेहतर रह सकता है।

हालांकि निगम अरोड़ा का कहना है कि इसमें थोड़ा समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि चांदी के औद्योगिक इस्तेमाल को देखते हुए मौजूदा परिदृश्य में इसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रह सकता है। लेकिन आगे इसमें तेजी आने की संभावना है।

कोरोनावायरस का साया पोल्ट्री उद्योग पर

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 4 मार्च

- कोरोनावायरस के भय से मुर्गीपालकों का बुरा हाल
- पोल्ट्री उत्पादों के दाम उत्पादन लागत से भी नीचे पहुंचे
- बहुत-से छोटे और असंगिठत कारोबारियों ने बंद किया कारोबार

कोरोनावायरस के प्रसार के भय से पोल्ट्री उत्पादों की उपभोक्ता मांग में भारी कमी आई है जिससे पिछले एक महीने के दौरान इनके दाम एक-तिहाई तक कम हो चुके हैं। बेंगलूरु के बेंचमार्क थोक बाजार में ब्रॉयलर चिकन के औसत दाम फरवरी में 61.76 रुपये प्रति किलोग्राम बोले गए हैं, जबकि जनवरी में दाम 91.58 रुपये प्रति किलोग्राम थे। हैदराबाद और बिहार के मुजफ्फरपुर के थोक बाजारों में फरवरी के दौरान मुर्गे की बिक्री क्रमश: 61.28 रुपये प्रति किलोग्राम और 78.66 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से हुई, जबकि जनवरी में दाम क्रमश: 86.28 रुपये प्रति किलोग्राम और 90.13 रुपये प्रति किलोग्राम थे। इस दौरान अंडे के भाव में भी कमी आई है। एक ओर जहां कोरोनावायरस के भय को पोल्ट्री उत्पादों के दामों में इस भारी गिरावट की वजह बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार और किसानों ने जोर देकर कहा है कि चिकन तथा अंडे के उपभोग का इस वायरस के प्रसार से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है।

वेंकीज ब्रांड के तहत पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री करने वाली कंपनी वेंकटश्वर हैचरीज के महाप्रबंधक केजी आनंद ने कहा, 'जब से कोरोनावायरस के प्रसार की खबरें आई हैं, तब से पोल्ट्री की खपत में तेज गिरावट देखी जा रही है। कोरोनावायरस का मुख्य स्रोत स्तनधारी जीव हैं, न कि पक्षी। लेकिन उपभोक्ताओं ने संभवत: एहतियाती तौर पर चिकन और अंडे की खरीदारी से दूरी बना ली, लिहाजा इनके दाम तेजी से लुढ़क गए।' आनंद के मुताबिक फिलहाल फार्म पर ब्रॉयलर चिकन का भाव 40 रुपये प्रति किलोग्राम बोला जा रहा है, जबकि इसकी उत्पादन लागत 80 से 85 रुपये प्रति किलोग्राम बैठती है। इसके परिणामस्वरूप मुर्गीपालकों को इस कारोबार में 50 फीसदी का नुकसान उठाना पड़ रहा है और इस क्षेत्र की बहुत-सी कंपनियां अपना कारोबार समेट चुकी हैं।

पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रमेश चंद्र खत्री ने कहा, 'चूंकि पोल्ट्री उद्योग में ज्यादातर छोटे और असंगठित खिलाड़ी हैं इसलिए वे इतना बड़ा नुकसान नहीं झेल सकते। लिहाजा वे अपनी उत्पादन क्षमता में कटौती कर रहे हैं। स्थिति यह है कि बहुत-से छोटे मुर्गीपालक अपना धंधा बंद करके आजीविका के दूसरे साधनों का रुख कर चुके हैं।' चारे की कीमतों में तेज उछाल के कारण मुर्गीपालक पिछले दो वर्ष से परेशान थे। अब चारे की कीमत में मामूली कमी आई, तो कोरोनावायरस के डर से खपत में आई कमी ने मुर्गीपालकों को करारा झटका दिया है।

इस बीच पिछले एक महीने में चारे का औसत भाव छह से 15 फीसदी तक कम हुआ है। फरवरी में सोयाबीन की औसत कीमत छह फीसदी घटकर 4,067 रुपये प्रति क्विंटल रह गई जो जनवरी में 4,329 रुपये प्रति क्विंटल थी। इसी तरह से मक्के और बाजरे की कीमतें भी फरवरी में क्रमश: 15 और आठ फीसदी घटकर 1,994 रुपये प्रति क्विंटल और 1,806 रुपये प्रति क्विंटल हो गईं जो जनवरी में क्रमश: 2,347 रुपये और 1,965 रुपये प्रति क्विंटल थीं। आनंद ने कहा, 'हमें दो महीने में मांग सामान्य होने की उम्मीद है, लेकिन तब तक गर्मी आ चुकी होगी जिसमें वैसे ही पोल्ट्री उत्पादों की मांग कमजोर बनी रहती है। लेकिन मुर्गे की कम उपलब्धता के कारण दामों पर कुछ सकारात्मक असर पड़ सकता है।'

पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक एक लाख करोड़ रुपये के पोल्ट्री उत्पाद क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर दो करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है।

कोरोना पर अब सरकार सतर्क

देश में अब तक वायरस संक्रमण के 28 मामले की पुष्टि की जा चुकी है

कोरोना पर बैठक करते हर्षवर्धन, विदेश मंत्री एस जयशंकर (दाएं)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को कहा कि देश में अब तक कोरोनावायरस से संक्रमण के 28 मामलों की पुष्टि हो गई है, इनमें इटली के 16 पर्यटक भी शामिल हैं। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि वायरस से पैदा हालात से निपटने के लिए सरकार पूरी तत्परता से सक्रिय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।

डॉ हर्षवर्धन ने कोरोनावायरस से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए एहतियाती उपायों की समीक्षा बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विदेश यात्रा कर भारत आने वाले सभी यात्रियों की हवाईअड्डों पर जांच की जाएगी। अब तक वायरस संक्रमण के दायरे वाले 12 देशों से भारत आने वाले यात्रियों की ही स्क्रीनिंग की जा रही थी।

उन्होंने लोगों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने और एक-दूसरे के सीधे संपर्क में आने से बचने की अपील की है। हर्षवर्धन ने कहा कि यदि ईरान की सरकार सहयोग के लिए तैयार होती है तो वहां भी एक जांच केंद्र बनाया जा सकता है ताकि भारत के नागरिकों को वापस लाने में मदद मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक ईरान में लगभग 1200 भारतीय नागरिक मौजूद हैं।

- **भारत में कुल संक्रमित लोगों में से इटली के 16 पर्यटक शामिल हैं**
- **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालात पर नजर बनाए हैं**
- **विदेश यात्रा से आने वाले यात्रियों की हवाईअड्डों पर जांच का दिया गया है आदेश**

बीमा का विकल्प

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बुधवार को कोरोनावायरस के दावे पर स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए। नियामक ने कहा कि मौजूदा योजनाओं में अस्पताल में भर्ती होने की लागत कवर होती है और कोरोनावायरस में भी यह नियम लागू होगा। उसने कहा कि बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करें कि वायरस से संबंधित मामले जल्द निपटाए जाएं। अगर कोरोनावायरस को डब्ल्यूएचओ या भारत सरकार महामारी घोषित करती है तब इन दावों का भुगतान नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसे दावे कई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी से बाहर हैं। *एजेंसियां*

सतर्कता बरततीं कंपनियां

पृष्ठ-1 का शेष

सूत्रों के अनुसार आईटी सेवा प्रदाता कंपनी विप्रो ने अपने परिसरों में स्थिति का जायजा लेने के लिए कई टीमों का गठन किया है। कंपनी के जो कर्मचारी पिछले कुछ दिनों में चीन से लौटे हैं, उन्हें अगले 14 दिनों तक घर से काम करने के लिए कहा गया है। कंपनी ने अपने एक बयान में कहा, 'विप्रो ने अपने कर्मचारियों की चीन यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है और चीन सहित हॉन्ग कॉन्ग और मकाऊ होकर यात्रा करने पर भी अस्थायी पाबंदी लगा दी है। कर्मचारियों को सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान और इटली की गैर-जरूरी यात्राएं टालने के लिए कहा है।' इंटेल ने भी बेंगलूरु में अपने कार्यालय में एहतिआत बरतना शुरू कर दिया है। कंपनी ने हरेक कॉन्फ्रेंस रूम सहित प्रवेश एवं निकास द्वारों पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की है। इंटेल के एक कर्मचारी ने कहा कि बाहर से जो भी वेंडर आ रहे हैं, उनकी पूरी जांच की जा रही है।

अमेरिका की आईटी कंपनी एरिस कम्युनिकेशंस ने नोएडा में अपने कार्यालय में अपने कर्मचारियों को एन 95 मास्क दे रही है। एफएमसीजी कंपनियां भी कोरोनावायरस के डर से पूरी सावधानी बरत रही हैं। फिक्की फ्रेम्स और क्रिकेट टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) जैसे बड़े कार्यक्रम अब तक टाले नहीं गए हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार फिक्की फ्रेम्स में भागीदारों की तादाद कम रह सकती है। आईपीएल 29 मार्च से शुरू हो रहा है।

पोलैंड में पहला मामला

पोलैंड और अर्जेंटीना के स्वास्थ्य मंत्री ने देश में कोरोनावायरस संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि की है। विश्व बैंक ने वायरस संक्रमण की वजह से स्वास्थ्य और आर्थिक स्तर पर जूझ रहे देशों की तत्काल मदद के लिए शुरुआती स्तर पर 12 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। कोरोनावायरस का संक्रमण अब 80 देशों में तेजी से फैल रहा है। फ्रांस में वायरस संक्रमण से चौथे व्यक्ति की मौत हो गई है जहां 212 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। वहीं अमेरिका में संक्रमित लोगों की तादाद 100 से अधिक हो गई है। वहीं जर्मनी में संक्रमण के 188 मामले की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान में कुल पांच लोगों के संक्रमित होने की खबर है। चीन से बाहर ईरान में वायरस का असर सबसे ज्यादा है जहां कुल 2336 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है और 77 लोगों की मौत हो चुकी है। सऊदी अरब ने भी बुधवार को उमरा स्थगित करने की घोषणा की

बैंकॉक में पर्यटक की जांच करते स्वास्थ्य अधिकारी

इटली में पिछले 24 घंटे में वायरस संक्रमण से 27 लोगों की मौत हो चुकी है जिससे मरने वालों की कुल तादाद 79 हो चुकी है और 2,502 लोग संक्रमित हैं। चीन में मरने वालों की कुल तादाद 2,981 हो गई है जबकि 80,270 लोग संक्रमित हैं। वैश्विक स्तर पर 93,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले की पुष्टि की गई है। बुधवार को दक्षिण कोरिया ने 9.8 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की जहां संक्रमण से जुड़े 516 नए मामलों की पुष्टि हुई है। बुधवार को एशियाई शेयरों में गिरावट जारी रही। कोरोनावायरस का प्रकोप बढ़ने के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने का डर सता रहा है ऐसे में अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया। *रॉयटर्स*

ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियां देंगी रिफंड

कोरोनावायरस महामारी के प्रसार का असर लोगों की यात्रा योजनाओं पर पड़ रहा है। कई कंपनियों और लोगों ने अपनी कारोबारी तथा निजी यात्रा की योजना टालने का फैसला किया है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियां भी टिकट कैंसिल कराने पर यात्रियों को रिफंड दे रही हैं। मेकमाईट्रिप के प्रवक्ता ने कहा कि विदेशी यात्रा की बुकिंग में मंदी देखी जा रही है क्योंकि यात्री अपनी विदेश योजना को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। कंपनी के कुल कारोबार में भारत से बाहर की यात्रा का कारोबार 20 फीसदी तक है। कंप[illegible] दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की बुकिंग [illegible] कमी देख रही है।

इसी तरह इक्सिगो ने क[illegible] देशों में फ्लाइट रद्द [illegible] सेवाएं [illegible]